(17) एक अन्य विवाद उठाया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने इल्जाम फ्रेमिंग को उस आदेश पर निर्भर किया जो सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा पारित किया गया जिसके तहत शिकायत को आगे की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया था और इसलिए यह स्वतंत्र दिमाग लागू करने में विफलता का खुलासा करता है, जो स्वीकारिया नहीं है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने केवल पूर्वोक्त आदेश का उल्लेख उदाहरण की तरह किया,जो यह सुझाव देता है की याचिकाकर्ता के खिलाफ चार्ज फ्रेम के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री पर्याप्त थी।

(18) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आदेश, किसी भी क्षेत्राधिकार या कानून की त्रुटि से पीड़ित नहीं है,जिसकी वजह से धारा 401 सीआरपीसी के तहत हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। उसे देखते हुए वर्तमान याचिका खारिज कर दी गई है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अवलोकन इस क्रम में विवाद के गुणों को छूता है, वह राय की अभिव्यक्ति नहीं माना जाता है।

आर.एन.आर.

*एस. एस. निज्जर, ए. स. जे और एस. एस. सरोन,*जे.जे. के समक्ष

मोहिन्दर *सिंह, – याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और & अन्य *– उत्तरदाता*

*सी.*डब्ल्यू.पी. *2005 की संख्या 6099*

12 अक्टूबर, 2006

भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद *226 – पंजाब सिविल सेवा (ई.बी.) नियम, 1930-- (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है) –* आर *1.3 – पंजाब सिविल सेवा (*केबी*) हरियाणा संशोधन नियम, 2002 –* आर *1.9-- 13 मई, 2005 को हरियाणा राज्य द्वारा जारी अधिसूचना –याचिकाकर्ताओं का चयन एच.सी.एस. (ई.बी.) --- नियुक्ति आदेश मॉडल आचार संहिता* केअनुसार नहीं जारिओ किए गए क्यूंकी चुनाव घोषित किए गए *-*मुकाबला *- याचिकाओं की पेंडेंसी के दौरान,सरकार* नोटफीकेशन द्वारा *कैडर की ताकत कम करना-1930 के नियमों की एक अधिसूचना* नियम 3*(2) सरकार को प्रदान* कर *हर 3 साल के अंतराल में कैडर की ताकत और संरचना की फिर से जांच की जाए और इसमें इस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं क्योंकि यह* सही *है - क्या कैडर की ताकत 3* साल *से पहले फिर से निर्धारित नहीं की जा सकती थी*

अंतिम अधिसूचना से – अभिनिर्धारित, सरकार किसी भी समय कैडर की ताकत और संरचना में 'परिवर्तन' करने की शक्ति नहीं रखता' - 'परिवर्तन' और `निर्धारित 'परिभाषित –' ऑल्टर 'का अर्थ है कुछ परिवर्तन – अधिसूचना दिनांक 13 मई, 2005 कैडर की ताकत में कोई कठोर बदलाव नहीं लाया गया–नियम.3 के तहत सरकार के पास कैडर की ताकत की समीक्षा करने की शक्ति है। नियम 3 के तहत 3 वर्ष एक अधिकतम अंतराल है जिसमें सरकार को कैडर की ताकत को फिर से परिभाषित करना है - सरकार का निर्णय कैडर की ताकत कम करना उचित है-नियुक्ति के लिए मात्र चयन एक कानूनी अधिकार नहीं बनाता है जिससे वह मंडमस की रिट लगाए – याचिकाकर्ता के पास एक अनिश्चित कानूनी अधिकार नहीं है, जो एक मंडमस की प्रकृति में एक रिट जारी लागू करवाए – अधिसूचना दिनांक 13 मई, 2005 को पूरी तरह से कानूनी और किसी भी कानूनी या न्यायसंगत दुर्बलता से पीड़ित नहीं है – प्रॉमिसरी एस्टॉपल के सिद्धांत अधिसूचना के लागू करने के खिलाफ – लागू नहीं - चयन प्रक्रिया में भाग लेने से याचिकाकर्ता को कोई नुकसान नहीं हुआ है या बहुत अधिक अपूरणीय क्षति हुई है– अधिसूचना द्वारा प्रासंगिक नियमों में कोई संशोधन नहीं– विज्ञापन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि भरे जाने वाले पदों की संख्या किसी भी सीमा तक भिन्नता के अधीन है –अधिसूचना दिनांक 13 मई, 2005 को बरकरार रखा गया – याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

अभिनिर्धारित, पंजाब सिविल के नियम 3 (1) (E.B.) नियम, 1930 यह दर्शाता है कि ताकत और सेवा की संरचना समय समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जानी है। नियम के किसी भी बाद के प्रावधान द्वारा यह खंड स्व-निहित है और नियंत्रित नहीं है। नियम 3 (2) यह बताता है कि सरकार कैडर की ताकत और संरचना की फिर से हर तीन साल के अंतराल पर जांच करेगी। इस खंड का मतलब यह नहीं है कि कैडर ताकत का कोई पुन: परीक्षण तीन साल से पहले नहीं हो सकता है। अधिक उचित व्याख्या होगी कि कैडर की ताकत और संरचना फिर से किसी भी समय सरकार द्वारा जांच हो सकती है। किसी भी कारण से, कुछ समय के लिए कैडर की कोई पुन: परीक्षा नहीं है, यह निश्चित रूप से हर तीन साल के अंतराल के बाद होगा। यदि फिर से तीन साल के अंतराल के बाद जांच की, सरकार इसमें परिवर्तन कर सकता है। यह व्याख्या स्वाभाविक रूप से नियम 3 से आती है। अगर कोई संदेह सरकार की फिर से जांच करने की ताकत को लेकर, एक विशेष पुनर्वितरण के बाद, वही निश्चित रूप से प्रोविज़ो द्वारा हटाया गया। यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि कुछ भी नहीं है मुख्य

नियम के लिए जो सरकार की किसी भी समय कैडर की ताकत और संरचना को प्रभावित करने के लिए समझा जाएगा। इसलिए सरकार के पास कैडर की ताकत की फिर से जांच करने और 13 मई, 2005 की अधिसूचना जारी करने की शक्ति थी। हम स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि कैडर की ताकत को 18 नवंबर 2003 को अंतिम अधिसूचना से तीन साल पहले निर्धारित नहीं किया जा सकता था। हम दिसंबर, 2006 तक सुबमिशनस को स्वीकार नहीं कर सकते, 18 नवंबर, 2003 को तय की गई कैडर की ताकत बरकरार रहेगी, 13 मई, 2005 की अधिसूचना के बावजूद। इसके अलावा, यह संभव नहीं होगा कि कैडर का पुनर्वितरण 13 मई, 2005 की अधिसूचना द्वारा, "बदलाव" या "परिवर्तन" की शब्दों के दायरे में नहीं आएगी, जैसा कि नियम 3 (2) और नियम 3 में परिकल्पित है।

(पैरा 22)

अभिनिर्धारित *किया,* यह रिकॉर्ड इस निष्कर्ष पर जाता है कि नई कैडर रिव्यू कमेटी बनाने की शायद ही कोई जरूरत थी। पहले की समिति द्वारा सुझाई गई ताकत 22 अप्रैल, 2004 के आदेश में दोहराया गया। नियम 3 के तहत कोई जनादेश नहीं है कैडर रिव्यू कमेटी के गठन के लिए सदस्यों की विशेष संख्या होनी चाहिए। वास्तव में, सदस्य सचिव जिन्होंने कैडर समीक्षा समिति के 18 नवंबर, 2003 की अधिसूचना के विचार-विमर्श में भाग लिया था, वही है जिन ने 22 अप्रैल, 2004 को नोटिंग की दी,जिसके आधार पर 13 मई, 2005 की अधिसूचना जारी की गई थी। समिति में सबसे जूनियर सदस्य थे। इसलिए, अपनी बात मनवाने के लिए उसने बहुत सतर्क और विनम्र भाषा अपनाई। परंतु उसी समय, उसने अपने वरिष्ठों को कोई शर्मिंदगी नहीं दी। अधिकारी के इस रवैये की प्रशंसा की जानी चाहिए और इसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए। यह निश्चित रूप से नोट की ईमानदारी पर संदेह पर एक लीवर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, हम इससे सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि किसी भी तरीके से नियम 3 का 13 मई, 2005 को अधिसूचना द्वारा कैडर की ताकत के निर्धारण में कोई उल्लंघन हुआ है।

(पैरा 27)

आगे अभिनिर्धारित, *याचिकाकर्ता के पास एक अनिश्चित कानूनी अधिकार नहीं है, जो एक मंडमस की प्रकृति में एक रिट जारी लागू* करवाए। वह सबमिशन जो विज्ञापित पदों पर नियुक्तियां देखने में करनी होंगी

2002 अधिनियम की धारा 4 में बिना पदार्थ के है। 2002 की ऐक्ट वास्तव में अधिनियम विज्ञापित से परे नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। यह आवश्यक रूप से नियुक्तियां करने के लिए विज्ञापित सभी पदों पर एक कानूनी कर्तव्य नहीं बनाता है। हम भी "प्रॉमिसरी एस्टॉपल " पर कोई पदार्थ नहीं पाते हैं। हमें इस पर संदेह है कि क्या "प्रॉमिसरी एस्टॉपल " के सिद्धांत 13 मई, 2005 की अधिसूचना के खिलाफ लागू होंगे। याचिकाकर्ताओं ने अपनी स्थिति को अपने नुकसान में बदल लिया है। किसी भी घटना में, वे भविष्य की किसी भी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कई, वास्तव में, पहले से ही अगले साल की चयन प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं। इसलिए, यह संभव नहीं है की याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में भाग लेने से किसी भी नुकसान या क्षति का सामना करना पड़ा या बहुत कम अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ा।

(पारस 34 और 36)

आगे अभिनिर्धारित, एक उम्मीदवार केवल आवेदन करके पोस्ट का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है। वह मौजूदा के नियम अनुसार, केवल चयन के लिए विचार किया जाना चाहिए। 13 मई, 2005 की अधिसूचना ने संबंधित नियमों में संशोधन में कोई बदलाव नहीं लाया। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का कोई भी अधिकार लेने का सवाल नहीं आता।

(पैरा 39)

आगे अभिनिर्धारित, 24 जनवरी, 2004 को विज्ञापन में स्पष्ट रूप से नोट (i) में प्रदान किया गया है कि "प्रत्येक के खिलाफ दिए गए पदों की संख्या श्रेणी किसी भी तरह से भिन्नता के लिए उत्तरदायी है ", यह खंड स्पष्ट रूप से संकेत देगा कि कोई भी उम्मीदवार किसी विशेष पद पर चुने जाने का निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। क्लॉज की अनुमति से पदों में भिन्नता किसी भी तरह से विस्तारित होती है। यह श्रेणीबद्ध है कि सभी याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन में निहित प्रॉमिसरी एस्टॉपल के मुताबिक नियमों और शर्तों पर भरोसा किया था। याचिकाकर्ताओं को उनके दावे के समर्थन में, विज्ञापन के भागों का चयन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर उनके पास है शर्तों के अनुसार चयन के लिए विचार करने का अधिकार है,क्यूंकी उनका अधिकार विज्ञापन के प्रकाशन पर क्रिस्टल है, एक दायित्व भी विज्ञापन का प्रकाशन पर आधारित है की उन्हे कम रिक्तियों की वजह से नहीं चुना जाएगा। यह प्राकृतिक अर्थ

नोट में निहित खंड (i) को दिया गया पदों की संख्या,
प्रत्येक श्रेणी के खिलाफ किसी भी तरह से भिन्नता के लिए उत्तरदायी है।

(पैरा 41)

जसपाल सिंह, सीनियर. अधिवक्ता जे.एस. दुहान, एडवोकेट.

जी.के. चतरथ, सीनियर. अलका चत्रथ, एडवोकेट के साथ

सीनियर. वकील. राजीव अत्मा राम, हेमराज मित्तल, एडवोकेट के साथ

पी. एस. पटवालिया, सीनियर. अधिवक्ता के साथ डी.एस. पटवालिया, एडवोकेट.

आर.के. मलिक, एडवोकेट और विवेक शर्मा, एडवोकेट.जगबीर मलिक, एडवोकेट.

वाई .पी. मलिक, एडवोकेट.

विवेक सूरी, एडवोकेट.

संदीप कोटला, एडवोकेट.

जी.पी. सिंह, एडवोकेट.

सी.बी. गोयल, एडवोकेट.

जी.एस. बाजवा, एडवोकेट.

जी.पी. सिंह, एडवोकेट.

हरि ओम अत्री, वकील *याचिकाकर्ता* के लिए।

एच.एस.हूडा, एडवोकेट जनरल, हरियाणा के साथ एम.एल.सागर,अतिरिक्त ए.जी., हरियाणा और पलिका मोंगा, एएजी, हरियाणा, *उत्तरदाता-राज्य* के लिए।

एच.एन. मेहतानी, एडवोकेट *प्रतिवादी के लिए - हरियाणा पब्लिक सेवा आयोग.*

निर्णय

एस.एस. निजजर , एसीजे

(१) याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुरोध पर, ये रिट याचिकाएँ (सिडब्लूपी न. 6099, 5437, 2839, 14371, 6258, 7683, 14317, 4818, 14370, 16951, 18572, 4457, 12540, 3768, 2005 के 2897) हैं गति चरण में अंतिम निपटान के लिए लिया गया. यह सामान्य निर्णय

तथ्यों के साथ-साथ सभी पूर्वोक्त रिट याचिकाओं का निपटान करेगा,क्योंकि कानूनी मुद्दे सभी रिट याचिकाओं में समान हैं।

(2) याचिकाकर्ता मैन्डैमस प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग करता हैं जिससे उत्तरदाता को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाए जो हरियाणा सिविल सर्विसेज [(कार्यकारी ब्राच) के लिए विधिवत चुने गए हैं (बाद में इसे "एचसीएस" कहा जाता है) (ईबी) "] और / या संबद्ध सेवाओं के लिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार – उत्तरदाता न. 2 (इसके बाद 30 दिसंबर, 2004 को "आयोग" के रूप में जाना जाता है)। याचिकाकर्ता ने केरटीओरारी की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए भी प्रार्थना की जिससे 13 मई, 2005 की अधिसूचना को रद्द करे जो हरियाणा राज्य द्वारा जारी(अनुबंध पी -1) उत्तरदाता नंबर 1– हरियाणा सिविल सर्विसेज (कार्यकारी शाखा) की कैडर ताकत है 300 से घटाकर 230 कर दिया गया।

(3) हम दलीलों से बाहर आवश्यक तथ्यों की दहलीज पर नोटिस कर सकते हैं, जो इन रिट याचिकाओं में विवाद के स्थगन के लिए प्रासंगिक हैं।

(4) याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने 24 जनवरी,2004 को उत्तरदाता न.1 और 2 द्वारा जारी एक विज्ञापन एचसीएस (ईबी) और संबद्ध सेवाओं में 102 रिक्त भरने के लिए जवाब में आवेदन किया था। एचसीएस की सेवा की भर्ती, नियुक्ति और शर्तें (EB) पंजाब सिविल सर्विसेज (कार्यकारी शाखा) द्वारा शासित नियम 1930, जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है (इसके बाद संदर्भित किया जाता है "1930 के नियम" के रूप में)। सेवा में नियुक्तियां आयोग की सिफारिशें पर की जाती हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार शामिल थी। चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया संलग्न अनुसूची में निहित पंजाब सिविल सर्विसेज (कार्यकारी शाखा) के रूप में जाना जाने वाला वैधानिक नियम हरियाणा संशोधन नियम, 2002 (बाद में इसे "2002" कहा जाता है नियम")है। विज्ञापन दिनांक 24 जनवरी, 2004 और बाद में चयन पूर्वोक्त 2002 नियमों के नियम 9 में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार आयोजित किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा 23 मई, 2004 को आयोजित की गई थी। मुख्य लिखित परीक्षा 1 अगस्तसे 10 अगस्त, 2004 तक आयोजित की गई थी। मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम 7 दिसंबर, 2004 को घोषित किया गया था। 15 दिसंबर, 2004 से 18 दिसंबर 2004 तक साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। परिणाम 30 दिसंबर, 2004 को घोषित किया गया था। जैसा कि पहले देखा गया था, सभी याचिकाकर्ताओं को घोषित किया गया था

उनका विधिवत चयन। इसलिए, उन्हें नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा थी जब भारत के चुनाव आयोग (बाद में "के रूप में जाना जाता है चुनाव आयोग ") ने हरियाणा राज्य में विधानसभा के चुनाव की घोषणा 17 दिसंबर, 2004 को कर दी। मतदान 3 फरवरी, 2005 को आयोजित किया जाना था। चुनाव आयोग 17 दिसंबर, 2004 को एक अधिसूचना भी जारी की गई, मॉडल आचार संहिता को चुनाव की अवधि के दौरान लागू किया गया। मॉडल आचार संहिता के खंड 3 (डी) में यह प्रावधान है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है, मंत्री और अन्य अधिकारी कोई अढोक नियुक्तियाँ नहीं करेंगे, जिससे सत्ता में पार्टी के पक्ष में मतदाताओं पर प्रभाव हो सकता है। अधिसूचना का खंड 4 ने चुनावों के संचालन से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह खंड 4 (vi) में आगे प्रदान किया गया है कि प्रतिबंध तब तक प्रभावी रहेगा चुनाव पूरा न हो जाए। 23 दिसंबर, 2004 को चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को एक और पत्र जारी किया निम्नलिखित दिशाओं के साथ: –

> आयोग ने इसलिए निर्देश दिया है कि राज्य
>
> सरकार नियुक्ति पत्र जारी नहीं करेगी,जब तक मॉडल आचार संहिता है। आयोग आगे निर्देश देता है कि यह आयोग के निर्देश को तुरंत लागू किया जाए और फैक्स द्वारा अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाए।
>
> आपका विश्वासपात्र,
>
> (एसडी।). .
>
> (के. अजाय कुमार),
>
> सचिव."

इस पत्र के बाद मुख्य सचिव को एक और पत्र दिया गया दिनांक 27 दिसंबर, 2004, जिसमें निम्नलिखित निर्देश थे: –

> मुझे स्पष्ट करने के लिए आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि आयोग द्वारा लगाई गई नियुक्तियों पर प्रतिबंध समान रूप से हरियाणा पब्लिक सेवा आयोग और / या किसी अन्य एजेंसी द्वारा चुने गए उम्मीदवारों पर लागू होता है

तदनुसार, आयोग ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार नियुक्तियों की पेशकश नहीं करेगी,जो हरियाणा लोक सेवा या किसी अन्य भर्ती एजेंसी द्वारा चुने गए, मंत्रालयों और विभागों की पूर्व अनुमति के बिना चुनाव पूरा होने तक। इस आशय के उपयुक्त निर्देश सभी संबंधितों को तुरंत जारी किया गया।"

(5) इन निर्देशों के जारी होने के बाद, हरियाणा राज्य चयनित उम्मीदवारों को नियुक्तियों की पेशकश नहीं की। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश के खिलाफ याचिका दायर करके इस न्यायालय से संपर्क किया। पेंडेंसी के दौरान इन रिट याचिकाओं में, हरियाणा राज्य ने अधिसूचना जारी की 13 मई, 2005 को,जिससे कैडर की ताकत सेवा में 300 से घटाकर 230 पद आ गई। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्वोक्त केवल उनके दावे को हराने के लिए अभ्यास किया गया है। इस प्रकार, रिट याचिकाओं में संशोधन किया गया है और अधिसूचना दिनांक 13 वीं माव, 2005 को भी चुनौती दी गई है।

(6) याचिकाकर्ताओं के लिए सभी विद्वान वकील में तर्क दिया कि यह सुनिश्चित करें कि उत्तरदाता ने अवैध रूप से और मनमाने ढंग से कैडर की ताकत 300 से 230 तक कम किया है। कैडर की ताकत में कमी,1930 के नियमों का उल्लंघन है। प्रक्रिया नियम 3 का पालन नहीं किया गया है। कैडर रिव्यू कमेटी को नहीं बनाया गया।

(7) श्री जसपाल सिंह, सीनियर वकील ने कहा कि 18 नवंबर,2003 को अधिसूचना द्वारा कैडर की ताकत तय की गई थी। दिसंबर, 2006 तक वही ताकत बरकरार रहनी थी, नियमों के तहत, कैडर ताकत की समीक्षा हर तीन साल में की जानी है। इसलिए, भले ही अधिसूचना दिनांक 13 मई, 2005 हो वैध माना जा सकता है, इसका केवल संभावित प्रभाव हो सकता है। यह रिक्तियों पर कैडर रिव्यू से पहले अस्तित्व में था जो 13 मई,2005 की अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाने वाले याचिकाकर्ताओं के निहित अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है। पूरा व्यायाम, वरिष्ठ वकील के अनुसार, माला *फाइड* है, और इसलिए, नुकसानदेह है। वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट के पी. महेंद्रन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (1) पर भरोसा किया है। वरिष्ठ वकील भी

---

(1) 1990 (1) एस.एस.सी411

रिक्तियों के विस्तृत चार्ट का संदर्भ दिया,जो वादों के साथ संलग्न किया गया है। इन चार्टों के अनुसार वरिष्ठ परिषद ने, स्पष्ट रूप से स्थापित करें कि रिक्तियां वास्तव में मौजूद हैं। चूंकि रिक्तियां उपलब्ध थीं, के निहित अधिकार नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए याचिकाकर्ताओं को दूर नहीं किया जा सकता था। वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट की एन.टी. डेविन कट्टी और अन्य *बनाम* कर्नाटका लोक सेवा आयोग और अन्य, (2) की टिप्पणियों पर निर्भर थे। वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि कुछ अधिकारी एक से अधिक पदों के कार्य कर रहे है। कुछ पोस्ट पर उन अधिकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया जो एचसीएस (ईबी) / संबद्ध से भी संबंधित नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, स्पष्ट रूप से स्थापित होगा कैडर की ताकत को 300 से 230 तक कम करने में उत्तरदाता की कार्यवाही एक आंख को धोने वाली है। याचिकाकर्ताओं के दावों को पराजित करने के लिए यह अभ्यास किया गया है।

(8) श्री जसपाल सिंह, वरिष्ठ वकील ने भी प्रस्तुत किया है परिवर्तन की आड़ में, उत्तरदाताओं ने कैडर की ताकत को पुनर्निर्धारित किया है। अधिसूचना 13 मई, 2005 बताती है कि यह 18 नवंबर, 2003 के आदेश के संशोधन में है। यह वास्तव में कैडर की ताकत और संरचना निर्धारित करता है 13 मई 2005 से 12 मई, 2008 तक तीन साल की अवधि के लिए करती है। वकील के अनुसार, "परिवर्तन" शब्द "बदलाव" का पर्याय नहीं है। शब्द "बदलाव " "एक चीज को दूसरे के साथ स्थानापन्न करने के लिए" है। जबकि "परिवर्तन" शब्द केवल "कुछ परिवर्तन" के साथ करना है"। इसलिए, नियम 3 (2) में "परिवर्तन" और 1930 के नियमों के अनंतिम का अर्थ है कैडर में भारी बदलाव नहीं।इसमें केवल कुछ बदलाव की परिकल्पना की गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि कैडर की संरचना मान्यता से परे हो सकती है। इस सबमिशन के समर्थन में, वरिष्ठ वकील ने पटना हाई कोर्ट के पूर्ण बेंच निर्णय फुलो सिंह और अन्य *बनाम* राज्य (3) तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय ज़मीर कासिम *बनाम* सम्राट (4) पर भरोसा किया। फुलो सिंह के मामले में *(सुपरा),* यह देखा गया कि :

> "(9)... कुछ के अनुसार, "परिवर्तन" शब्द बहुत व्यापक महत्व रखता है, जबकि, दूसरों के अनुसार, यह कहीं अधिक सीमित है "रिवर्स" शब्द से,जो व्यक्त किया गया है। "

(2) (1990) 3 एस.सी.सी. 157

(3) एआईआर1956 पटना 170 (F.B.)

(4) एआईआर (31) 1944 ऑल। 137 (एफ.बी.)

इलाहाबाद हाई के फुल बेंच मामले में बहुमत का मानना है कि "परिवर्तन" शब्द "रिवर्स" शब्द की तुलना में कम कट्टरपंथी है और इसका अर्थ है " प्रपत्र में परिवर्तन "के अंतर्निहित चरित्र को बदलने के बिना बात बदलनी है। उस मामले में असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण ऐसा प्रतीत होता है कि "परिवर्तन" शब्द का उपयोग ऐसे किया गया है कि इसका तात्पर्य है कि परिवर्तन "रीवर्स" की तुलना में बहुत सीमित दायरे की एक प्रक्रिया है।"

XXX XXX XXX

शब्द "परिवर्तन" का केवल कुछ परिवर्तन के साथ करना है, जबकि रूप, आकार या आकृति को बनाए रखना है। इसमें इसका "संशोधित" शब्द के समान अर्थ और "रिवर्स" जैसे, `एनल" या "अवशेष"का विरोध किया है। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय बहुमत का दृष्टिकोण, इतना लंबा जैसा कि वाक्य में वृद्धि नहीं हुई है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि बरी करने के आदेश को प्रतिस्थापित किया गया है सजा के आदेश, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ।"

(9) भेद पर जोर देने के लिए, वरिष्ठ वकील ने "परिवर्तन, बदलाव और निर्धारित" शब्दों के संबंध में प्रविष्टियों पर भरोसा किया" जैसा कि रैंडम हाउस अनब्रिज्ड डिक्शनरी (न्यूली) संशोधित और अद्यतन) दिया गया है। पूर्वोक्त प्रविष्टियाँ इस प्रकार हैं के तहत: –

""ऑल्टर, वी.टी. 1. आकार के रूप में कुछ विशेष में अलग बनाने के लिए, शैली, पाठ्यक्रम, या पसंद; संशोधित; कोट; एक इच्छा को बदलने के लिए; सेवा पाठ्यक्रम में परिवर्तन. 3. बदलने के लिए, अलग हो जाएं या [1350-1400; एमई < अल्टेरर का < एल एल बिगड़ने के लिए, व्युत्पन्न. का एल परिवर्तन अन्य } -alter.er, एन-Syn. 1. समायोजित देखें, बदलें.

परिवर्तन, एन. 1. परिवर्तन का कार्य, परिवर्तित होने की स्थिति: परिवर्तन पोशाक को साबित करता है. 2. एक परिवर्तन, संशोधन या निर्धारित करना, निर्धारण करना-एन. 2. कुछ निर्धारित करता है. 3. एक को निरूपित करने के लिए वैचारिक लेखन में प्रयुक्त ग्राफिक प्रतीक शब्दार्थ वर्ग और एक शब्द में लिखा है कि क्या इंगित करें शब्दार्थ श्रेणी शब्द को समझना है, इस प्रकार कई बार अलग-अलग होमोग्राफ.

निर्धारित 1. दृढ़; कट्टर; निर्धारित रक्षकों अलामो का. 2. का फैसला किया; बसे हुए; हल किया. 3. ग्राम। (एक का ध्वन्यात्मक विशेषता) इसके आसपास के संदर्भ से अनुमानित है.

वरिष्ठ वकील ने कहा कि कैडर की ताकत के पुनर्वितरण के लिए पहला अभ्यास वर्ष 1990 में किया गया था। नियम 3 का उल्लंघन तब किया गया जब ताकत 300 से घटाकर 230 कर दी गई पहले यह 240 था। यह, वरिष्ठ वकील के अनुसार, परिवर्तन नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा यह परिवर्तन केवल एक निश्चित मात्रा में भिन्नता की अनुमति देगा। वह ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी में निहित "भिन्नता" शब्द की परिभाषा पर निर्भर करता है जो इस प्रकार है: –

"भिन्नता :

3. स्थिति, चरित्र, डिग्री, आदि में भिन्नता का कार्य समय या दूरी, या कई उदाहरणों के बीच; तथ्य परिवर्तन या परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, esp। कुछ के भीतर सीमाएँ: इस की डिग्री या राशि.

4. अलग होने या बदलने का एक उदाहरण; किसी चीज में बदलाव, esp। कुछ सीमाओं के भीतर; कुछ बदलाव के कारण अंतर या परिवर्तन ई 17.

6. कार्यवाही या कुछ परिवर्तन या परिवर्तन करने का एक कार्य, esp. (कानून) एक आदेश, विश्वास, अनुबंध आदि के संदर्भ में."

(10) याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि याचिकाकर्ता को नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सभी वकील इस बात पर सहमत हुए कि याचिकाकर्ता के पास नियुक्त होने का अनिश्चित अधिकार नहीं है। हालांकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता को केवल याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति से इनकार करने के लिए मनमाने ढंग से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाता जानबूझकर पिछली सरकार शासन के दौरान की गई चयन के रूप में नियुक्ति को इनकार कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील ने नियम 3 के तहत राज्य सरकार को दी गई शक्ति हरियाणा सिविल सर्विसेज (ईबी) और संबद्ध सेवा के प्रावधान और अन्य सेवाएँ सामान्य / संयुक्त परीक्षा अधिनियम, 2002 (इसके बाद) जिसे "2002 अधिनियम" कहा जाता है) को हरा नहीं सकती। वरिष्ठ वकील के अनुसार, 2002 अधिनियम की धारा 4 (1) के आधार पर, कोई नियुक्ति विज्ञापित पदों से परे किसी भी पद या सेवा के लिए नहीं की जा सकती है। धारा 4 (2) किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री या कानून की अदालत के निर्णय, अधिनियम, नियम, विनियमन या कार्यकारी निर्देशों के विरुद्ध नहीं, विज्ञापित पदों की संख्या से परे उम्मीदवार को नियुक्ति लेने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का विधिवत चयन किया गया है विज्ञापित पदों के खिलाफ नियुक्त होने का अधिकार होगा।

(11) श्री जसपाल सिंह, वरिष्ठ वकील भी प्रॉमिसरी एस्टॉपल के आधार पर याचिकाकर्ता न्यायसंगत पर नियुक्ति पाने के हकदार हैं। इस सबमिशन के समर्थन में वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट के शिम सिंह और अन्य *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य (5)पर और दिल्ली की डिवीजन बेंच के कनिष्क अग्रवाल *बनाम* विश्वविद्यालय दिल्ली और अन्य (6)पर भरोसा किया।

(12) श्री चत्रथ याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रदर्शित होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता 2005 के ओएटी नंबर 14371,द्वारा कुछ अतिरिक्त बिंदु भी उठाए गए। वरिष्ठ वकील ने श्री जसपाल सिंह द्वारा उन्नत तर्कों को अपनाया। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया उत्तरदाता कि दलील न केवल पतनशील हैं, बल्कि रिकॉर्ड के खिलाफ है। उत्तरदाता ने गलत तरीके से कहा है कि 48 पदों में वृद्धि की गई थी कैडर एचसीएस के उदाहरण पर (EB) अधिकारी संघ (Regd.)। वास्तव में इन 48 पदों में से 35 को बरकरार रखा गया है। 1990 से पहले की पोस्ट के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया है। उच्च कर्तव्य निचले कैडर के अधिकारियों को दिया गया। रजिस्टरों से सभी नामांकित व्यक्ति ए -I, ए-II और रजिस्टर सी नियुक्त किए गए हैं। केवल रजिस्टर बी के खिलाफ उम्मीदवारों का चयन, परिणामस्वरूप, नियुक्तियों से वंचित कर दिया गया। तथ्यात्मक रूप से, उन्होंने प्रस्तुत किया कि रिक्तियां अभी भी उपलब्ध है जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया जा सकता है। प्रक्रिया नियमों के तहत निर्धारित सावधानीपूर्वक पालन किया जाना है। समर्थन में इस सबमिशन के बारे में, वरिष्ठ वकील सर्वोच्च न्यायालय के उत्तर प्रदेश राज्य *बनाम* सिंघारा सिंह और अन्य, (7), हुकम चंद श्याम लाल *बनाम* भारत संघ और अन्य, (8), चंद्र किशोर झा *बनाम* महावीर प्रसाद और अन्य, (9), एम.एस. एहलवात *बनाम* राज्य हरियाणा और अन्य (10) पर भरोसा किया। वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किए कि आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सामान्य परिस्थितियों में, आयोग की सिफारिशों को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए और मायला *फ़ाइड* के सिद्ध के अभाव में स्वीकार किया गया। इसके समर्थन में

(5) (1981) 2 एस.सी.सी. 673

(6) आकाशवाणी 1992 दिल्ली 105

(7) एआईआर 1964 एस.सी. 358

(8) एआईआर 1976 एस.सी. 789

(9) जेटी 1999 (7) एस.सी. 256

(10) जेटी 1999 (8) एस.सी. 530

प्रस्तुत करना, वरिष्ठ वकील एक डिवीजन बेंच के मामले राज कुमारी *बनाम* राज्य पंजाब और अन्य, (11)पर और इस अदालत का एक एकल बेंच निर्णय परमवीर सिंह और अन्य *बनाम* पंजाब राज्य और अन्य, (12)पर भरोसा करता है। एक बिदाई शॉट के रूप में, वकील ने सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय इंदरप्रीत सिंह कहलॉन और अन्य *बनाम* पंजाब राज्य और अन्य, (13)पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि सतर्कता या सी.बी.आई. जांच याचिकाकर्ताओं को नियुक्तियों से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा निर्णय केवल जांच पूरी होने पर लिया जा सकता है; वह भी, उसके बाद ही याचिकाकर्ता को मिलने का अवसर देना, कोई प्रतिकूल निष्कर्ष जांच में दर्ज किया जा सकता है।

(13) वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि इस के पूर्ण बेंच निर्णय पर उत्तरदाताओं द्वारा रखी गई निर्भरता के मामले में कोर्ट अमरबीर सिंह और अन्य *बनाम* राज्य का पंजाब और अन्य, (14) गलत है. पूर्वोक्त निर्णय को विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शासित किया गया है.

(14) श्री राजीव आत्मा राम, वरिष्ठ अधिवक्ता याचिकाकर्ता 2005 के सीडब्ल्यूपी न. 5437 की ओर से,श्री जसपाल सिंह के तर्कों को अपनाते है। हालाँकि, उसने विस्तृत स्वतंत्र प्रस्तुतियाँ भी की है। वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि मॉडल कोड के खंड 7 (iv) (डी) के तहत चुनाव के लिए आचरण, केवल एक *तदर्थ* नियुक्ति नहीं की जा सकती। नियमित आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। वरिष्ठ वकील ने डिवीजन बेंच के बबीता गुप्ता *बनाम* पंजाब राज्य और अन्य (15), और सर्वोच्च न्यायालय के आई.जे. दिवाकर और अन्य *बनाम* आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य, (16) फैसले पर भरोसा किया। वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि नियुक्ति जब एक बार के लिए आयोग को भेजा गया बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। पूर्वोक्त मामले में, एक दिशा चयन पूरा करने और नियुक्तियां करने के लिए दिया गया था. यह

---

(11) 2005 (1) एस.सी.टी. 287

(12) 2003 (4) आर.एस.जे. 162

(13) जेटी 2006 (5) एस.सी. 352

(14) 2003 (5) एस.एल.आर. 398

(15) 1998 (4) आर.एस.जे. 408

(16) एआईआर 1982 एस.सी. 1555

आगे निर्देशित किया गया था कि केवल सूची में कुछ न मिलने पर अन्य नियुक्तियां की जा सकती थीं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने दोहराया कि कानूनी औचित्य के बिना नियुक्तियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। वह आर.एस. मित्तल *बनाम* भारत संघ, (17) फैसले पर निर्भर था। वरिष्ठ वकील ने आगे दोहराया कि भले ही कैडर की समीक्षा को स्वीकार किया जाता है, रिक्तियां अभी भी उपलब्ध हैं जिनके खिलाफ याचिकाकर्ता हैं नियुक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1930 के नियमों के अनुसार 28 रिक्तियों के एक ब्लॉक में, 19 प्रत्यक्ष नियुक्ति के हिस्से में गिर जाएगा। यह उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है कि सेवा में प्रोमोटीस ज्यादा काम कर रहे हैं। हालांकि, उत्तरदाता ने निवेदन किया कि पिछली सरकार द्वारा कैडर ताकत की अवास्तविक मुद्रास्फीति से अतिरिक्त है । वरिष्ठ वकील ने बताया कि इस मामले में विभिन्न रजिस्टर के उम्मीदवारों के लिए भी प्रत्यक्ष भर्ती खुली है। पिछली सरकार के आदेशों की शुद्धता को यह वर्तमान सरकार चुनौती क्योंकि वह पहले ही कार्यालय के पारित किए गए आदेश थे और अब वर्तमान रिट याचिका में वह खुद उत्तरदाता है। प्रस्ताव के बारे में, वरिष्ठ वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के असम का राज्य और अन्य *बनाम* राघव राजगोपालाचारी, (18), और दिल्ली हाई कोर्ट के जोगिंदर पाल सिंह *बनाम* भारत का संघ और अन्य, (19) और इस न्यायालय के पंजाब पर्यटन विकास निगम *बनाम* पीठासीन अधिकारी, लेबर कोर्ट, अमृतसर और अन्य, (20) पर भरोसा किया। वरिष्ठ वकील ने इसके बाद नियुक्तियों के इनकार के प्रतिकूल प्रभावों और इस स्तर पर याचिकाकर्ता पर क्या प्रभाव होगा उस पर जोर दिया। वे प्रतिकूल रूप से उनका वेतन, वरिष्ठता और अनुभव का लाभ का निर्णय लेने में प्रभावित होंगे। उसने यह कहा कि इस मामले में नियुक्तियों पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश नहीं चाहिए अन्यथा चयनित उम्मीदवारों को मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने मामले में दिए गए इस न्यायालय के पूर्ण बेंच के सुखदेव सिंह सिद्धू और अन्य *बनाम* पंजाब राज्य और अन्य, (21) पर भरोसा किया। वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि कार्यकारी शाखा में 37 पदों पर नियुक्ति सभी 44 पदों पर कैडर की समीक्षा के आधार पर संबद्ध सेवाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कैडर की समीक्षा केवल कुछ निश्चित पदों तक सीमित है <u>जो</u>

(17) जे.टी. 1995 (3) एस.सी. 417

(18) 1972 एस.एल.आर. 44

(19) 1983 (3) एस.एल.आर. 252

(20) 1997 (1) ए.आई.जे. 15

(21) 2003 (3) आर.एस.जे. 299

कार्यकारी शाखा में है। उस चयन की आज तक कोई विदारक खोज नहीं है। अभी भी पूछताछ चल रही है। अनियमितताओं के आरोप याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय के एक डिवीजन बेंच के गिरिश अरोड़ा *बनाम* हरियाणा राज्य, (22) फैसले पर भरोसा किया। कैडर की मनमानी को वरिष्ठ वकील ने दोहराते हुए प्रस्तुत किया कि इस व्यायाम में, जो पोस्ट प्रत्यक्ष भर्तियों के हिस्से में आते हैं, उन्हें जानबूझकर बढ़ावा देने के लिए कम किया गया है। अन्यथा, कोटा से अधिक काम करने वाले लोगों को वापस करना होगा। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कैडर की समीक्षा को करीब से देखने पर पता चलता हैं कि हटाए गए पोस्ट वे पोस्ट नहीं हैं जिनके बारे में आरोप लगाया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई दलील इसलिए रिकॉर्ड के खिलाफ है। उत्तरदाता का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वह याचिकाकर्ता को नियुक्ति से इनकार करे। चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्रों में दिए गए निर्देश 2004 के 23, 24 और 27 दिसंबर उनके अधिकार क्षेत्र से परे हैं। चुनाव कराने के लिए मॉडल आचार संहिता नियुक्तियो पर नियमित नहीं होती है। यह केवल *तदर्थ* नियुक्तियों पर लगती है।

(15) श्री पी.एस. पटवालिया, वरिष्ठ वकील 2005 के संशोधित सीडब्ल्यूपी न. 2839 में याचिकाकर्ता की ओर से भी पहले के वकील के तर्कों को सुनते है। श्री पटवालिया, वरिष्ठ वकील ने एक शिकायत की,कि जो चुनाव से पहले की गई थी, उस पर घोषणा की गई थी कि राजनीतिक रैलियों के साथ-साथ अखबारों में भी कि अगर कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि शासन के समय के चयन के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं करेगा। यह, तदनुसार वरिष्ठ वकील के लिए, एक स्पष्ट संकेतक है कि पूरे कैडर की ताकत में कमी का व्यायाम *माला फाइड* है। यह केवल नियुक्ति के याचिकाकर्ताओं को वंचित करने के बाद किया गया है। उसने आगे प्रस्तुत किया है यह आरोप कि आयोग के माध्यम से चयन जल्दी किया गया है, रिकॉर्ड के विपरीत है। वरिष्ठ वकील ने बताया 2002 के नियमों के आधार पर चयन किया गया है जो 30 सितंबर, 2002 को प्रकाशित हुए हैं। इनके तहत नियम, समय सीमा निर्धारित है। इन नियमों के अनुसार, पहले वर्ष 2003 में चयन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में चयन को चुनौती दी गई थी। हरियाणा राज्य ने दायर किया हलफनामा बताते हुए

(22) 1997 (3) एस.सी.टी. 240

समय सीमा का अनुपालन किया जाएगा। नियम 3 प्रत्येक वर्ष के लिए योजना निर्धारित करता है। अंतरिम प्रवास के कारण परिणाम घोषित नहीं किया गया था इस अदालत द्वारा दी गई जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खाली कर दिया गया था। इस प्रकार, परिणाम 30 दिसंबर, 2004 को घोषित किया गया था। साथ में कैडर ताकत की जानबूझकर मुद्रास्फीति के संबंध में, वरिष्ठ वकील ने कहा कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। 2003 में, कुल 48 पद जोड़े गए। इसके अलावा, आज भी 35 पद मौजूद हैं। सरकार ने उन पदों को भी समाप्त कर दिया है जो 1990 से जारी थे। किसी भी मामले में, भले ही कैडर कम हो, फिर भी 11 पद खाली है। उत्तरदाता ने स्वयं निवेदन किया है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए 10 पद रखे गए हैं। कुछ याचिकाकर्ता रखे जा सकते हैं,अगर वर्तमान सरकार कार्य को एक उचित और सही तरीके से करे।

(16) श्री आर.के. मलिक, 2005 के सीडब्ल्यूपी न. 2897 में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए , उन्होंने कहा कि भले ही कैडर में पद समाप्त कर दिया जाए, यह एक कार्यात्मक उन्मूलन होना चाहिए और उल्लेखनीय नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव के समर्थन में, वकील ने इस न्यायालय के एक डिवीजन बेंच के प्रेम चंद, नायब तहसीलर *बनाम* हरियाणा राज्य, (23) के फैसले पर भरोसा किया। वर्तमान मामला में, पदों का उन्मूलन केवल एक कागज-लेन-देन है। इन पदों के कार्य में वृद्धि हुई है। अतिरिक्त शुल्क कई प्रचार अधिकारियों को दिया गया है। ये अधिकारी प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए पोस्ट पर कब्जा कर रहे हैं । वकील ने आगे कहा कि भले ही कैडर 300 से 230 तक कम हो, फिर भी नियुक्तियों को 230 पदों पर बने, तब भी 156 पद प्रत्यक्ष भर्तियों के हिस्से में आते थे। इसके खिलाफ केवल 119 प्रत्यक्ष भर्ती काम कर रहे हैं। इसलिए, कम ताकत के आधार पर भी 37 और नियुक्तियां की जा सकती हैं। वकील ने कहा कि कोई याचिकाकर्ता को अनंतिम नियुक्ति से इनकार करने का औचित्य नहीं है, सब जांच के परिणाम के अधीन हैं। कार्यवही उत्तरदाता द्वारा खराब की गई है मालाय *फाइड* और मनमानी है। वकील के अनुसार, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का पूर्ण निषेध है।

(17) दूसरी ओर, श्री एच.एस. हूडा, एडवोकेट जनरल, हरियाणा ने प्रस्तुत किया कि सरकार के पास कैडर ताकत की समीक्षा करने की शक्ति है। आयोग द्वारा सिफारिशें 27 दिसंबर, 2004 के पत्र के बाद भी की गईं, जो चुनाव

आयोग ने भेजा था। इसके अलावा, बड़ी संख्या में रिट याचिकाएं दायर की गई हैं आरोप लगाया कि चयन को प्रशिक्षित किया गया था। अब याचिकाकर्ताओं ने दायर की है वर्तमान रिट याचिकाएँ। 1930 के नियमों का उल्लेख करते हुए, विद्वान महाधिवक्ता ने कहा कि नियम 3 व्यापक शक्ति देता है कि सरकार तीन साल के भीतर भी कैडर की समीक्षा करे। नियम समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। सरकार के पास कैडर का पुनर्गठन करने का पूर्ण विवेक है। ऐसा कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है। यह सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि है। कैडर का पुनर्निर्धारण ताकत एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक अभ्यास है जिसके परिणामस्वरूप विशुद्ध रूप से प्रशासनिक आदेश है। उस समय जब निर्णय लिया गया था 300 से 230 तक कैडर की ताकत को फिर से परिभाषित करने के लिए, याचिकाकर्ता के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इसलिए मैन्डैमस द्वारा यह न्यायालय निर्देश देता है कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया जाए। नियुक्तियां निस्संदेह नियमों के अनुसार होंगी। विद्वान महाधिवक्ता ने आगे कहा कि उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया निर्णय में मनमानी नहीं है। लेकिन इस मामले में विस्तृत कारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं, जिन्हें उपलब्ध कराया गया है। वह आगे कहता है कि एक सचेत और जिम्मेदार निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है। इसके अलावा, कैडर का पुनर्वितरण, नियमों के तहत सावधानीपूर्वक पालन की योजना रही है। भौतिक तथ्यों को ध्यान में रखा गया है। न्यायिक समीक्षा में न्यायालय केवल जांच करेंगे निर्णय लेने की प्रक्रिया और योग्यता पर निर्णय की जांच नहीं करेगा। निर्णय, संबंधित सामग्री के उचित विचार पर आधारित होता है, इसे मनमाना, मक्कार या रंगीन व्यायाम नहीं कहा जा सकता है। एडवोकेट जनरल ने आगे कहा कि कैडर ताकत कम हो गई क्योंकि कैडर की ताकत आई.ए.एस. राज्य में कम हो गया था। पहले कैडर रिव्यू कमेटी ने शुरू में कैडर की ताकत 180 की सिफारिश की थी। तब अभ्यावेदन 48 पदों की वृद्धि के लिए एचसीएस (ईबी) अधिकारियों से प्राप्त किया गया। ये बिना किसी औचित्य के, पिछले शासन द्वारा स्वीकार किया गया। अंततः, कैडर की ताकत 300 तक बढ़ गई थी। इसलिए, एक सचेत निर्णय कैडर ताकत पर पुनर्विचार करने के लिए लिया गया। सरकार ने अब कैडर की ताकत 230 पर तय की है। दूसरे शब्दों में, सरकार ने पहले की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। वहां एक ताजा कैडर समीक्षा समिति को पुनर्गठित करने की आवश्यकता नहीं है। पहले कैडर रिव्यू कमेटी ने कैडर की ताकत 230 तय की थी। यह प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने वाली सरकार पर 300 तक बढ़ गया 'आईसीएस अधिकारी और तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ।

महाधिवक्ता ने जोर दिया कि कानून के सिद्धांत के रूप में, मंडमस की प्रकृति में नियुक्तियों के लिए रिट जारी नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ताओं का कोई कानूनी अधिकार नहीं उल्लंघन किया गया है। कानून के उपरोक्त प्रस्ताव के समर्थन में महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता दिखाई-

(1) हरियाणा राज्य *बनाम* सुभाश चंदर मारवाहा और अन्य (24) ;

(2) मणि सुब्रत जैन और अन्य *बनाम* राज्य का हरियाणा और अन्य (25) ;

(3) जतिंदर कुमार और अन्य *बनाम* पंजाब राज्य और अन्य (26) ;

(4) शंकरन डैश *बनाम* भारत संघ (27) ;

(5) डॉ. एच. मुखर्जी *बनाम* भारत संघ और अन्य (28) ;

(6) डॉ. पी.के. जैसवाल *बनाम* सुश्री डेबी मुखर्जी और अन्य (29) ;

(7) गिरिश अरोड़ा और अन्य *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य (30) ;

(8) लुधियाना सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि. *बनाम* अमरीक सिंह और अन्य (31) ;

(9) हाशनी कुमार *बनाम* पंजाब राज्य और अन्य (३२) ;

(10) सुनीता रानी और अन्य *बनाम* पंजाब राज्य और अन्य (33) ;

(11) भूपेंद्र सिंह *बनाम* हरियाणा राज्य, (34) ;

(24) (1974) 3 एस.सी.सी. 220

(25) 1977 (1) एस.सी.सी. 486

(26) (1985) 1 एस.सी.सी. 122

(27) (1991) 3 एस.सी.सी. 47

(28) 1994 सप। (1) एस.सी.सी. 250

(29) (1992) 2 एस.सी.सी. 148

(30) 1997 (5) एस.एल.आर. 660

(31) (2003) 10 एस.सी.सी. 136

(32) 2004 (7) एस.एल.आर. 793

(33) 2005 (1) आर.एस.जे. 712

(34) 2004 (3) आर.एस.जे. 724

(12) हरियाणा राज्य आदि. *बनाम* सत्य पार्काश आदि.(35)

(13) एस.एस.धनोआ *बनाम* भारत संघ और अन्य(36) ;

(14) एस.पार्टप सिंह *बनाम* पंजाब राज्य, (37) ;

(15) ई .पी. रॉयप्पा *बनाम* तमिलनाडु राज्य और अन्य , (38);•

(16) वाई .कटोंच *बनाम* भारत संघ और अन्य (39) ;

(17) एन. रमनथा पिल्लई *बनाम* केरल राज्य, (40) ;

(18) म/स मोतीलाल पद्मावत चीनी मिल्स कंपनी. लिमिटेड. *बनाम* उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (41) ;

(19) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम *बनाम* एस.पी. सिंह और अन्य, (42) ;

(20) डॉ. अशोक कुमार महेश्वरी *बनाम* यू.पी. राज्य. और दूसरा, (43) ;

(21) हरबन्स सिंह जलाल, पूर्व विधायक, बठिंडा *बनाम* भारत संघ, (44) तथा

(22) परीक्षा का नियंत्रक के माध्यम से हरियाणा लोक सेवा आयोग *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य (45).

(18) जतिंदर कुमार *(*सुपरा*)* के मामले में की गई टिप्पणियों पर भरोसा कर महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि सरकार विधानमंडल के प्रति जवाबदेह है, यदि वह आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए निर्णय नहीं लेती है। सरकार द्वारा विधानमंडल को कारण दिए जाने हैं। इसलिए, यह नहीं हो सकता

(35) 1990 (1) पी.एल.आर. 352

(36) जेटी 1991 (3) एस.सी. 290

(37) एआईआर 1964 एस.सी. 72 .

(38) आकाशवाणी 1974 एस.सी. 555

(39) 2003 (3) आर.एस.जे. 474

(40) एआईआर 1973 एस.सी. 2641

(41) एआईआर 1979 एस.सी. 621

(42) एआईआर 1998 एस.सी. 2779

(43) एआईआर 1998 एस.सी. 966

(44) (1997) 2 पी.एल.आर.778

(45) 2005 (3) पी.एल.आर.486

यहां तक कि कहा जाता है कि सरकार में पूर्ण शक्ति निहित है सिफारिशों को स्वीकार करने या न करने के लिए। सिफारिशों के मामले में सरकार द्वारा अपनाया गया आयोग स्वीकार नहीं किया जाता है, अनुच्छेद 320 उप-लेख (3) भारत के संविधान में दिया गया है। पूर्वोक्त प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। कारणों को औपचारिकताओं के पूरा होने पर विधानमंडल को उपलब्ध कराया जाएगा। तथ्यात्मक रूप से, महाधिवक्ता यह स्वीकार करता है कि याचिकाकर्ताओं को नौकरी नहीं दी जा सकती क्योंकि वे बस मौजूद नहीं है। किसी भी घटना में, जांच अभी भी लंबित है। मंडमस की प्रकृति के लिए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

(19) श्री मेहतानी, के लिए प्रदर्शित होने वाले वकील आयोग ने प्रस्तुत किया कि आवश्यकता के अनुसार सिफारिशें की गई हैं। उस समय जब सिफारिशें नियुक्ति के लिए, तब रिक्तियों का अस्तित्व था। वकील के अनुसार, बाद की घटनाओं से कैडर की ताकत प्रभावित नहीं होगी। राज्य ने विरोधाभासी रुख अपनाया है। उन्होंने वह आरोप प्रस्तुत किया आयोग के खिलाफ केवल चयन को रद्द करना है। वह मामले में दिए गए इस न्यायालय के पूर्ण बेंच निर्णय पर निर्भर जस्करन सिंह बराड़ *बनाम* पंजाब राज्य और अन्य, (46)पर भरोसा किया। वकील ने आगे कहा कि सरकार मना कर सकती है केवल दुर्लभ सिफारिशों को स्वीकार करने के मामलों में। वर्तमान मामले में सरकार की कार्यवाही को पदावनत करना होगा। यह सरकार से इसका स्वतंत्र कामकाज को ओवरव्यू करने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। वकील ने आगे कहा कि चुनाव मॉडल आचार संहिता नियमित चयन को कवर नहीं कर रही।अधिसूचना अढोक चयन के *विज्ञापन* से संबंधित है। चयन निष्पक्ष है। चयन अनियमितताओं के साथ दागी नहीं था। हरियाणा प्रतिवादी-राज्य ने किसी भी सामग्री को आगे नहीं दिखाया जो चयन को दागी दिखाए। इस कोर्ट के डिवीजन बेंच वकील गिरिश अरोरा के मामले में *(*सुपरा*)* के फैसले पर भरोसा किया गया। वकील के अनुसार, प्रासंगिक सिद्धांतों उक्त निर्णय के पैरा 36 में शामिल किया गया है।

(20) जवाब में, श्री हुडा, एडवोकेट जनरल ने कहा कि माला फाइड के अभाव में प्रस्तुत किया, कोर्ट को सरकार का निर्णय में हस्तक्षेप से बचना होगा। उसके अनुसार

के सामान्य आरोप *माला फाइड* उचित से परे साबित किया जाने का शक है। इस प्रस्ताव के समर्थन में, महाधिवक्ता मामलों में प्रदान किए गए सर्वोच्च न्यायालय के एस.प्रताप सिंह *(सुपरा),* ई.पी. रॉयप्पा *(सुपरा)* और इस न्यायालय के डिविशन बेंच ने वाई. कटोंच *(सुपरा)* के मामले में प्रस्तुत किया है। निर्णयों पर निर्भर महाधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया किसी विशेष पद को समाप्त किया जाना है या नहीं, यह एक नीति का निर्णय है, और इसलिए, रिट कार्यवाही में हटाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट एन. रामनाथन पिइलाई *(सुपरा).* के फैसले पर भरोसा किया, तर्कों को दोहराते हुए एस्टोपेल पर श्री जसपाल सिंह, एडवोकेट जनरल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय *मिस* मोतीलाल पद्मप सुगर मिल्स कंपनी. लिमिटेड. *(सुपरा)* पर निर्भर थे। वकील ने प्रस्तुत किया चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देश अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त नहीं हैं।

(21) हमने विद्वान वकील के तर्कों पर ध्यान दिया है पार्टियों के लिए बहुत विस्तृत रूप से जैसा कि इस मामले में तर्क दिया गया था। जैसा कि निर्णय के पहले भाग में देखा गया है, राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा एक जांच पहले से ही कुछ असफल उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई याचिकाएं में आदेश दिया गया है। हमारे पास इन मामलों को स्थगित करने का प्रस्ताव साइन डाई भी था, पर किसी भी जांच का निष्कर्ष सूचीबद्ध किया जाना है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने सख्ती से तर्क दिया कि वर्तमान मामलों में कोई जांच का आदेश नहीं दिया गया है और योग्यता के आधार पर रिट याचिकाओं को सुना जा सकता है।

(22) यद्यपि हमने प्रत्येक व्यक्ति के तर्कों पर ध्यान दिया है वकील, स्वतंत्र रूप से और विस्तृत रूप से, यह आवश्यक नहीं होगा उन्हें व्यक्तिगत रूप से विचार करें। उन सभी पर एक साथ विचार किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकील का पहला तर्क है कैडर ताकत की अवैध कमी। पार्टियों की विनती से, यह उभर कर आता है कि कैडर की ताकत और संरचना समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका अभ्यास कर रहे सरकार ने 7 नवंबर, 1990 को 240 पदों पर कैडर की ताकत निर्धारित की। 20 अक्टूबर, 1999 पर अगली समीक्षा समिति ने फिर से 240 पदों पर कैडर की ताकत तय की। फिर 25 मई, 2001 को सरकार की राय थी कि एचसीएस की कैडर ताकत को लगभग 210 पदों तक कम करने की आवश्यकता है। फिर वर्ष 2002 में नियम 3 के तहत कैडर की ताकत की समीक्षा की गई थी। कैडर रिव्यू कमेटी से अनुरोध किया गया था कि वह 17 पदों को जोड़े

एच.सी.एस. (ईबी) ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व (Regd।)। कैडर रिव्यू कमेटी ने केवल आठ पदों को स्वीकार किया। कैडर की ताकत 223 पर निर्धारित की गई थी। फिर से पूर्वोक्त एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व, कैडर में 48 पद जोड़े गए। हालाँकि, 26 पोस्ट हटा दिए गए थे। वास्तविक कैडर निर्धारित किया गया था 180 पर और भर्ती के लिए कैडर की ताकत 271 पर निर्धारित की गई थी। इसके बाद 20 और पदों को जोड़ा गया। स्थायी कैडर 200 बनाया गया था और भर्ती की ताकत 300 पर तय की गई थी। इसके बाद 20 और पद जोड़े गए। युक्तिकरण करने के बाद व्यायाम, सरकार ने आदेश द्वारा कैडर की ताकत को 230 पर तय किया दिनांक 13 मई, 2005। पूर्वोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि तर्क याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से गलत धारणा पर आधारित हैं कि कैडर ताकत कम हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कैडर की ताकत है 1990 के बाद से 180 से 230 पदों के बीच रहा। इसलिए, विद्वान वकील की अधीनता को स्वीकार करना संभव नहीं है कि अधिसूचना 13 मई, 2005 को तय करने के उत्तरदाताओं द्वारा कैडर की ताकत जारी करने में कोई अनुचित मकसद रहा है। हम यह भी कहने में असमर्थ हैं कि पुनर्वितरण और कैडर ताकत का निर्धारण नियम 3 के विपरीत है। 1930 के नियम 3 के तहत प्रदान करता है: –

> "3. कैडर की ताकत (1) और रचना हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) कैडर करेगा इस तरह से सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जा सकता है।
>
> (2) सरकार हर तीन साल के अंतराल पर, हरियाणा की ताकत और संरचना की फिर से जांच करें सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) कैडर और बना सकते हैं इस तरह के परिवर्तन के रूप में यह फिट बैठता है।
>
> बशर्ते कि इस नियम में कुछ भी प्रभावित सरकार की शक्ति और किसी भी समय कैडर की ताकत बदलने के लिए नहीं समझा जाएगा।"

नियम 3 (1) का पक्षाघात यह दर्शाता है कि ताकत और सेवा की संरचना सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जानी है। यह खंड स्व-निहित है और नियंत्रित नहीं है, प्रावधान द्वारा 3 (2) कि पोस्ट सरकार हर तीन साल में की ताकत और संरचना की फिर से जांच करेगी। इस खंड को पढ़ा नहीं जा सकता

इसका मतलब यह है कि वहाँ हो सकता है कि कैडर ताकत की फिर से जांच तीन साल से पहले नहीं हुई हो। हमारी राय में, अधिक उचित व्याख्या यह सुझाव देना होगा कि कैडर की एक रचना की ताकत किसी भी समय सरकार द्वारा फिर से जांच की जा सकती है। किसी मामले में किसी कारण के लिए, कुछ समय के लिए कैडर की पुन: परीक्षा नहीं ली गई, यह निश्चित रूप से हर तीन साल के अंतराल के बाद किया जाना चाहिए। अगर फिर सेतीन साल के अंतराल पर, सरकार मानती है इसमें कोई भी परिवर्तन करने के लिए फिट है, ऐसा हो सकता है। यह व्याख्या स्वाभाविक रूप से नियम 3 से पढ़ा जाता है। अगर इसमें कोई शक है,फिर से जांच करने के लिए सरकार की शक्ति के संबंध में तीन साल से पहले कैडर, एक विशेष पुनर्वितरण के बाद, वही निश्चित रूप से प्रोविज़ो द्वारा हटा दिया जाता है। यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि मुख्य नियम में कुछ भी शक्ति को प्रभावित करने के लिए नहीं समझा जाएगा, जो कैडर की ताकत और संरचना को किसी भी समय बदल दे (जोर दिया गया)। इसलिए, 13 मई, 2005 को अधिसूचना से हम मानते हैं कैडर ताकत की फिर से जांच करने और जारी करने की शक्ति सरकार के पास थी। हम श्री जसपाल सिंह की सबमिशन स्वीकार करने में असमर्थ हैं के कैडर की ताकत को पिछले तीन साल से अधिसूचना दिनांक 18 नवंबर, 2003के पहले से पुनर्निर्धारित नहीं किया जा सकता था। हम स्वीकार नहीं कर सकते दिसंबर, 2006 तक, कैडर की ताकत 18 नवंबर, 2003 तय की गई , वही 13 मई, 2005 की अधिसूचना के बावजूद बरकरार रहेगा। इसके अलावा, यह संभव नहीं होगा अधिसूचना द्वारा कैडर की ताकत का पुनर्वितरण दिनांकित 13 मई, 2005 "परिवर्तन" की शर्तों के दायरे में नहीं आएगा या नियम 3 (2) के तहत परिकल्पित के रूप में "परिवर्तन" और नियम के लिए 3. हमारे पास परिभाषाओं की शुद्धता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है शब्द "परिवर्तन" और "भिन्नता" जैसा कि रैंडम में दिया गया है सदन शब्दकोश (सुपरा) और परिभाषा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में निहित "भिन्नता" शब्द है। पटना उच्च न्यायालय ने बहुमत से इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूरी बेंच के दृष्टिकोण को नोट किया है। उसी का एक अनुमान दिखाता हैं कि शब्द "परिवर्तन" की व्याख्या "उलटा" शब्द के विपरीत की गई है। शब्द "रिवर्स" को "एनुल" या "अवशेष" जैसे शब्दों के बराबर किया गया है जबकि "परिवर्तन" शब्द का अर्थ केवल अर्थ के लिए व्यक्त किया गया है। चीज़ के अंतर्निहित चरित्र को बदलने के बिना कुछ परिवर्तन बदला जाना है। हालाँकि, श्री जसपाल सिंह द्वारा सामने रखे गए मामले के लिए इन टिप्पणियों से कोई सहायता नहीं होगी। हमारी राय हैं कि 13 मई, 2005 की अधिसूचना में कोई कमी नहीं आई है

वो भी कैडर की ताकत में। यह कृत्रिम मुद्रास्फीति से पहले की कैडर समीक्षा समिति के 60 पदों के निर्णय को पुष्ट करता है । श्री जसपाल सिंह और अन्य वकील की उपस्थिति को स्वीकार करना भी संभव नहीं है चूंकि कोई कैडर समीक्षा समिति नहीं थी। 13 मई, 2005 की अधिसूचना नियम 3 के गैर-अनुपालन में है। हमने पहले अधिसूचना में 13 मई,2005 को पुनरावृत्ति को पुन: पेश किया है। यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि नियम 3 के तहत राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। कैडर की ताकत तीन साल की अवधि के लिए निर्धारित की गई थी यानी 13 मई, 2005 से 12 मई, 2008 तक। हमारा विचार है कि नियम 3 के तहत सरकार द्वारा प्राप्त व्यापक शक्तियों के मद्देनजर किसी भी समय कैडर की ताकत की समीक्षा करने के लिए, तारीखों को सब कुछ नहीं माना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 12 मई,2008 के बाद की सरकार कैडर को फिर से निर्धारित करने के लिए शक्तिहीन होगी। जैसा कि पहले से ही हमारे द्वारा देखा गया है, नियम 3 के तहत प्रदान किए गए वर्ष एक अधिकतम अंतराल है जिसके भीतर सरकार को कैडर की ताकत को फिर से परिभाषित करना होगा। निर्धारित अवधि न्यूनतम नहीं है। हम श्री जसपाल सिंह की सबमिशन से सहमत नहीं हैं कि अधिसूचना दिनांक 13 मई, 2005 को सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया था। राज्यपाल के नाम की अधिसूचना, सरकार की अधिसूचना नहीं बन जाएगी। दरअसल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत, एक राज्य सरकार की सभी कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर व्यक्त किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, हम श्री जसपाल सिंह के तर्कों से प्रभावित नहीं हैं कि 13 मई, 2005 की अधिसूचना सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है और इसके लिए भी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम श्री हुदा, विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं। वादों और रिकॉर्ड ने यह प्रदर्शित किया है कि चूंकि कैडर रिव्यू कमेटी द्वारा की गई मूल सिफारिश 240 पदों के सम्मान को स्वीकार किया गया था, एक गठन की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, हमारी राय है कि नियम 3 के तहत, शक्ति और संरचना का निर्धारण करने की शक्ति सरकार में कैडर निहित है और किसी विशेष में नहीं। कैडर रिव्यू कमेटी केवल सरकार की एक उचित शक्ति का सुझाव देने के लिए साधन कैडर है। अंतिम निर्णय सरकार को लेना होगा। यह

यह भी आई. ए. एस का एक निर्विवाद तथ्य है। अधिकारियों को 10 पदों से कम कर दिया था। इसलिए, 230 पदों पर कैडर की ताकत तय करना सनकी या तर्कहीन नहीं कहा जाएगा । सरकार ने कैडर के पुनर्वितरण के लिए सचेत निर्णय, सामान्य परिस्थितियों में लिया है, जिससे न्यायालय की हस्तक्षेप करने की बहुत कम गुंजाइश होगी।

(23) निस्संदेह, न्यायालय न्यायिक शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से माला *फाइड* सिद्ध मामलों में किया जा सकता है, मनमानी, या जहां अप्रासंगिक विचार भौतिक रूप से कार्यकारी निर्णय को प्रभावित करते हो। इन शक्तियों का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया का जांच करना है, निर्णय की योग्यता ही नहीं। शक्ति के दायरे और दायरे के संबंध में अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की बड़े पैमाने पर जांच की गई है। एस.पी. गुप्ता *बनाम* भारत संघ और दूसरा, (47),में सुप्रीम कोर्ट ने देखा है के रूप में: –

> ""न्यायालय का यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि *लोक स्टैंडी* और औचित्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर है और यह कि सार्वजनिक राज्य की ओर से हर डिफ़ॉल्ट उचित नहीं है। न्यायालय को ध्यान रखना चाहिए कि यह अपने न्यायिक कार्य की सीमाओं से अधिक न जाए और उन क्षेत्रों में अतिचार न करे जो कार्यकारी के लिए आरक्षित हैं और संविधान द्वारा विधानमंडल...."

टाटा सेलुलर *बनाम* भारत संघ, (48),में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विचार किया और दी *लॉर्ड ब्राइटमैन* ने मुख्य नॉर्थ वेल्स पुलिस के कांस्टेबल *बनाम* इवांस, (49) टिप्पणियों को मंजूरी दी। पूर्वोक्त निर्णय के पैरा 91 में, सुप्रीम कोर्ट ने देखा निम्नानुसार: –

> "91. न्यायिक समीक्षा योग्यता की समीक्षा नहीं करने से संबंधित है,जिसके लिए आवेदन न्यायिक समीक्षा की जाती है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया की समीक्षा करती है।"

---

(47) 1981 (Suppl) S.C.C. 87

(48) जे.टी. 1994 (4) एस.सी. 532

(49) (1982) 3 ऑल। E.R. 141

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के अनुच्छेद 95 में अनुपात को और भी स्पष्ट कर दिया: –

"95. इसलिए, यह अदालत को निर्धारित नहीं करना कि क्या विशेष नीति या विशेष रूप से उसका लिया गया निर्णय उचित है या नहीं। इसका संबंध केवल तरीके से है जैसे यह फैसला लिया गया है। निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए कर्तव्य की सीमा मामले से अलग-अलग होगी। शीघ्र ही, वह आधार जिस पर एक प्रशासनिक कार्यवाही न्यायिक समीक्षा द्वारा नियंत्रण के अधीन हो सकती है के वर्गीकृत है: –

(i) अवैधता: – इसका मतलब है कि निर्णय लेने वाले को सही ढंग से उस कानून को समझना, जो उसे नियंत्रित करता है और निर्णय को प्रभाव देना चाहिए।

(ii) तर्कहीनता, अर्थात्, वेसेनबरी अपरंपरागतता।

(iii) प्रक्रियात्मक अक्षमता।"

(24) पूर्वोक्त परीक्षण लागू करते हुए, हमने हरियाणा राज्य द्वारा उत्पादित कैडर की ताकत में कमी के संबंध में जांच की है। हरियाणा राज्य द्वारा, बिना किसी हिचकिचाहट के ,पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया है। श्री जसपाल सिंह और अन्य वकीलों याचिकाकर्ताओं की ओर से, को 10 नवंबर,2005 के आदेश द्वारा रिकॉर्ड की जांच करने की अनुमति दी गई थी। इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया।

(25) परामर्श याचिकाकर्ताओं के लिए यह दलील प्रस्तुत की कि हरियाणा राज्य द्वारा कहा गया कि पिछली सरकार द्वारा कैडर अनावश्यक रूप से फुलाया गया रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं है। सरकार ऐसे किसी निर्णय पर नहीं पहुंची थी। उन्होंने 22 अप्रैल,2005 को कैडर की कमी के आदेश का विशेष संदर्भ किया। श्री जसपाल सिंह ने प्रस्तुत किया नोट की भाषा गैर-कमिटेड भाषा का एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने निम्नलिखित के लिए एक विशेष संदर्भ दिया: –

"यह मामला एचसीएस (ईबी) कैडर की ताकत तय करने के बारे में है। अंतिम कैडर समीक्षा वर्ष में आयोजित की गई थी 2003 जब इस कैडर की ताकत 240 से बढ़ाई गई थी एक बार में 300 तक। कैडर प्रबंधन का मुद्दा और

उन विकृतियों को दूर करने की आवश्यकता है, जिनमें दरारें, सेवा के बहुत भारी, अनिच्छुक आकार के कारण है। कैडर की ताकत को एक नए रूप की आवश्यकता है।

जैसा कि सर्वविदित है कि कैडर में किसी भी पद को बनाने के लिए प्रशासन में काम की आवश्यकता को देखें और व्यय को पूरा करने के लिए धन की उपलब्धता को देखें। ऐसा करते समय, पूर्ण औचित्य की आवश्यकता होती है। सरकार का सामान्य अभ्यास यह है कि जब काम की आवश्यकता होती है, पोस्ट को एक वर्ष और अस्थायी आधार पर बनाया जाता है निरंतरता की समीक्षा हर साल की जाती है और यदि यह पाया जाता है काम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पद के लिए आवश्यक है फिर इसे एक और वर्ष तक जारी रखने की अनुमति मिल जाती है। आमतौर पर एक पद को पांच साल की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर जारी रखने की अनुमति है और फिर इसे समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है के इसे स्थायी पद में बदले या नहीं। ऐसा करते हुए मार्गदर्शक कारक काम की आवश्यकता है और इसमें शामिल व्यय भी। हो सकता है, 2003 में ये कैडर की समीक्षा के लिए गठित समिति द्वारा विचार किया गया हो। हालांकि, यह भी महसूस किया जाता है कि एक और विश्लेषणात्मक और गहन अभ्यास की आवश्यकता थी जो शायद उस समय नहीं किया जा सकता था। यह महसूस किया जाता है कि शायद विभिन्न विभागों के कार्य का मूल्यांकन नहीं किया गया और पूरा डेटा / जानकारी की अनुपस्थिति में समिति को विश्लेषणात्मक कार्य अध्ययन के लाभ के बिना करना था।"

श्री जसपाल सिंह के अनुसार, पूर्वोक्त अर्क यह निष्कर्ष नहीं निकालता है कि इसके द्वारा एक जानबूझकर प्रयास किया गया है पिछली सरकार द्वारा कैडर की ताकत बढ़ाने के लिए। हमारी राय है कि वरिष्ठ वकील आदेश का आकलन करने में घोर अनुचित है जो 22 अप्रैल, 2005 को विशेष सचिव राजनीतिक द्वारा पारित किया गया था। यदि कोई पूरे नोट को पढ़ता है, तो स्पष्ट तस्वीर उभरती है पूरा मामला जो उत्तरदाताओं द्वारा लिखित में निर्धारित किया गया है। वास्तव में आदेश वादों की तुलना में बहुत अधिक निर्णायक है। हमारी राय में, आधिकारिक रिकॉर्ड के नोटिंग हिस्से को संदर्भित किया गया है। श्री जसपाल सिंह ने भी अन्यथा नहीं याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई कानूनी अधिकार बनाएं है। सर्वोच्च न्यायालय

ने पुरंजीत सिंह *बनाम* संघ का क्षेत्र चंडीगढ़ और अन्य, (50) स्पष्ट रूप से निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

> "6..... हालांकि, कानून में स्पष्ट स्थिति के बावजूद, वह अपने सहायक अभियंता के नए कैरियर से पहले की वरिष्ठता की गिनती के लिए गलत दावे का पीछा कर रहा था और पदोन्नति के लिए वह संगठन में अर्जित पदोन्नति का सहारा ले रहा था जो उसे प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। इस उद्देश्य के लिए, मुख्य अभियंता या कुछ विशेष सूचनाओं पर चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव पर वह भरोसा कर रहा है। हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि उक्त अधिसूचनाओं उसके कब्जे में कैसे आए , लेकिन इन उत्पादन के लिए उसकी ओर से अनुचित था और वो भी यह मानते हुए कि उसके पास यह सब अधिकृत रूप से है। एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में उसे यह जानना चाहिए कि विभागीय फाइलों में क्या है और उसने उनके पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाया। यह आदेश सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया गया और उसके द्वारा प्राप्त किया गया जो अकेले ही उसके पक्ष में अधिकार पैदा कर सकता है। यह अलग है कि उन सूचनाओं से कोई उनके पक्ष का आदेश पास नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में, जिस पर याचिकाकर्ता का वकील निर्भर हैं,उस का इन तथ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।"

(26) कानून के उपरोक्त अनुपात को देखते हुए, श्री जसपाल सिंह की प्रस्तुतियों को बिना किसी और विचार के खारिज किया जा सकता था। हालांकि, न्याय के हित में, हमने प्रासंगिक रिकार्ड की जांच की है। हालांकि, न्यायालय बाकी आदेशों पर विस्तार से टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि हरियाणा राज्य के गठन के बाद से कैडर में भर्ती का पूरा इतिहास आदेश रिकॉर्ड करता है। इसमें इंगित किए गए स्पष्ट निष्कर्ष आदेश हैं कि: –

(a) वर्ष 1972 से 2000 तक, कैडर में वार्षिक सेवन 10 से 20 था, वर्ष 1980 को छोड़कर जब वहाँ केवल 25 एचसीएस अधिकारी थे ;

(b) 2002 और 2003 के वर्षों में, संयुक्त परीक्षा के कारण सेवन 58 था।

(50) 1994(5) एस. एल. आर. 280

(c) हालांकि पिछले 39 वर्षों से यानी की स्थापना के बाद से कैडर की ताकत लगभग 240 रही है।

(d) कैडर में अधिकारियों की वास्तविक ताकत काफी वर्षों से 200 से नीचे है।

(e) यह केवल हाल ही में कैडर में लगभग 220 अधिकारी थे। इतने वर्षों से एचसीएस की कोई अतिरिक्त किसी भी तिमाही से, मांग नहीं थी।

(f) एचसीएस अधिकारियों की प्रचलित और प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। किए गए कार्य की आवश्यकता के विश्लेषण से पता चलता है कि 240 पदों की वर्तमान ताकत उच्च पक्ष पर है।

(g) यहां तक कि ध्यान में रखते हुए, छुट्टी या प्रशिक्षण के प्रावधान, अधिकतम आवश्यकता 250 पद होगी, लेकिन 250 हरियाणा राज्य के भीतर पद उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार, एचसीएस राज्य की एक प्रमुख सेवा है, कोई भी अत्यधिक भर्ती राज्य पर एक सरासर अपशिष्ट या नाली होगी सरकारी खजाने से।

(h) कैडर की ताकत की समीक्षा वर्ष 1999 में की गई थी और, सभी प्रासंगिक कारकों / पहलुओं को लेने के बाद विचार, यह तय किया गया था कि कोई आवश्यकता नहीं थी कैडर की ताकत बढ़ाएं।

(i) वर्ष 2003 में फिर से कैडर की ताकत की समीक्षा से 60 पोस्ट जोड़े गए।

(j) इन चार वर्षों यानी 1999 से 2003 के दौरान, प्रशासन में ऐसी कोई बात नहीं हुई, जिस पर अधिक एचसीएस अधिकारियों के लिए वारंट होना चाहिए।

(k) विभिन्न विभागों में राज्य की गतिविधियाँ व्यावहारिक रूप से वही थी जो वर्ष 1999 में थी।

(l) इस अवधि के दौरान, कोई नया विभाग या उपक्रम सरकार नहीं बनाएगी, जिसके लिए एचसीएस अधिकारियों की सेवाएं की आवश्यकता हो।

(m) इसलिए, इस कैडर में 60 पदों के अलावा ऐसा लगता है कृत्रिम उचित नहीं है (जोर दिया गया)।

पूर्वोक्त कारणों को दर्ज करने के बाद, विशेष सचिव के तहत अंतिम निष्कर्ष दिया:

–

"यह परीक्षा स्पष्ट करती है कि एचसीएस कैडर में वृद्धि ताकत कृत्रिम है और इसके अनुरूप प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। 60 का अतिरिक्त वर्ष 2003 में किए गए पदों को दूर किया जा सकता है और एचसीएस (ई.बी.) कैडर की ताकत 230 पर तय की जा सकती है, जैसा कि एनपी -32 पर प्रति विवरण। "

(27) हमारी राय में, सरकार द्वारा लिए गए निष्कर्ष का कारण उचित हैं। पूर्वोक्त विशेष सचिव द्वारा सीएम के सामने रखे तर्क को 29 अप्रैल,2005 में मंजूरी दे दी गई। रिकॉर्ड यह इंगित करता है कैडर रिव्यू कमेटी जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा बहुत कुछ कहा गया था, वह 25 जून,2003 को हरियाणा के गवर्नर के आदेश द्वारा गठित किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष, दो सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल थे। चारों IAS अधिकारी थे। सभापति 72 वें बैच के थे। दोनों सदस्य 75 वें बैच और सचिव 85 वें बैच के थे। समिति ने केवल दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति की पहली बैठक 1 जुलाई, 2003 को आयोजित की गई थी। 2 जुलाई, 2003 को सभी वित्तीय आयुक्तों और प्रधान सचिवों और हरियाणा सरकार के प्रशासनिक सचिव को एक नोटिस जारी किया गया था। एचसीएस (ईबी) अधिकारियों की आवश्यकताओं का आकलन करने का अनुरोध किया विभागों और सदस्य सचिव को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। समिति ने 20 अगस्त,2003 को एक सर्वसम्मत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कैडर का अंतिम मूल्यांकन जैसा कि पहले देखा गया था, 230 पद का हैं। इसे मुख्यमंत्री के विशिष्ट आदेश पर बढ़ाकर 300 कर दिया गया। इसलिए, हमारी राय में, रिकॉर्ड भी निष्कर्ष की ओर जाता है कि नई कैडर रिव्यू कमेटी बनाने की शायद ही कोई जरूरत थी। पहले की समिति द्वारा सुझाई गई ताकत महज थी, जो 22 अप्रैल, 2004 के आदेश में दोहराया गया था। कैडर रिव्यू कमेटी के गठन के लिए नियम 3 के तहत सदस्यों की एक विशेष संख्या कोई जनादेश नहीं है । वास्तव में, कैडर समीक्षा समिति के विचार-विमर्श में भाग लेने वाले सदस्य सचिव का समापन हुआ 18 नवंबर, 2003 की अधिसूचना समान है अधिकारी जिन्होंने अब 22 अप्रैल, 2004 को नोटिंग की है जिसके आधार पर 13 मई, 2005 की अधिसूचना जारी की गई है।

वह समिति के कनिष्ठ-अधिकांश सदस्य थे। इसलिए, अपनी बात मनवाने के लिए उसने बहुत सतर्क और विनम्र भाषा अपनाई। परंतु उसी समय, उसने अपने वरिष्ठों को कोई शर्मिंदगी नहीं होने दी। अधिकारी के इस रवैये की प्रशंसा की जानी चाहिए और इसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए। यह निश्चित रूप से प्रभावकारिता और संदेह पर एक लीवर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए, श्री जसपाल सिंह को प्रस्तुत करना कि नियम का कोई उल्लंघन है कैडर ताकत के निर्धारण में किसी भी तरीके से 3 अधिसूचना द्वारा दिनांक 13 मई, 2005,हम इससे सहमत नहीं हो पा रहे हैं।

(28) याचिकाकर्ता के वकील की सब्मिस्शन के राज्य सरकार के 230 पदों पर कैडर की ताकत तय करने का निर्णय मालया फाइड द्वारा खारिज हो गया है से सहमत नहीं है। हमारी राय में, विद्वान एडवोकेट जनरल ने सही तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के एस. भागप सिंह *(सुपरा)* पर भरोसा किया है। पूर्वोक्त निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है निम्नानुसार: –

> "8. निस्संदेह, जो किसी भी अधिनियम को अमान्य या अशक्त करना चाहता है उसे आदेश को बुरे विश्वास, दुर्व्यवहार या इसकी शक्तियों का सरकार द्वारा दुरुपयोग को स्थापित करना चाहिए। जबकि अप्रत्यक्ष मकसद या उद्देश्य या बुरा विश्वास या व्यक्तिगत बीमार-स्पष्ट प्रमाण को छोड़कर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद, इंसान के दिमाग की स्थापना करना स्पष्ट रूप से कठिन है, उसके लिए अपीलकर्ता को इस मामले को स्थापित करना है, हालांकि यह कभी-कभी हो सकता है(एडिंगटन देखें *बनाम* फिट्ज़मौरिस, (1884) 29 Ch D459)। यह कहने से कठिनाई कम नहीं होती है कि एक मंत्री स्पष्ट रूप से सत्ता के वैध अभ्यास में अभिनय कर रहा है ताकि वह एक नाजायज उद्देश्य का पीछा कर सके। हालाँकि, हमें निंदा करनी चाहिए ऐसे सुझाव कि जी कहता है कि *माला फाइड* के मकसद को केवल प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए, जो लगाए गए आदेश से विवेकी होना चाहिए या फ़ाइल में नोटिंग से दिखाया जाना चाहिए। यदि बुरा विश्वास आदेश को समाप्त कर देगा, हमारी राय में, उचित के रूप में कटौती की जा सकती है और सिद्ध तथ्यों से अपरिहार्य निष्कर्ष पाया जा सकता है।"

(29) सर्वोच्च न्यायालय ने ई.पी. रॉयप्पा *(सुपरा)* के नियम को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया है: –

> **"92. दूसरी बात, हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मालया फाइड को साबित करने का बोझ उसी पर आता है, जो व्यक्ति यह आरोप लगाता है। मालया फाइड के आरोप अक्सर साबित की तुलना में आसानी से लगाए जाते है, और इस तरह के गंभीर आरोप साख के उच्च क्रम के प्रमाण की मांग करते हैं। "**

(30) कैडर के 230 पद की ताकत के निर्धारण को सही ठहराने के, विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा ने सर्वोच्च न्यायालय के एन. रमनाथा पिल्लई *(सुपरा)* में की गई टिप्पणियों पर निर्भरता रखी है। सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार कहता है: -

> **"14. पहला सवाल जो निर्धारण के लिए आता है, वह है सरकार को सेवा में एक पद को समाप्त करने का अधिकार है। किसी पद को बनाने या समाप्त करने की शक्ति संबंधित नहीं है। यह सरकारी नीति का मामला है। प्रत्येक संप्रभु सरकार के हित में उसकी शक्ति और आंतरिक प्रशासन की आवश्यकता है। निर्माण या पद का उन्मूलन नीतिगत निर्णय, परिस्थितियों और प्रशासनिक आवश्यकता, शर्तों से तय होता है । सृष्टि, निरंतरता और पद का उन्मूलन, प्रशासन और आम जनता के हित में सरकार द्वारा तय किए जाते हैं ।"**

(31) पदों के निर्माण और उन्मूलन के संबंध में कानून था फिर से सुप्रीम कोर्ट एस. एस. धनोआ *बनाम* संघ का भारत और *अन्य (सुपरा)* में दोहराया गया। निर्णय के पैराग्राफ 30 में, यह स्पष्ट रूप से निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

> **"30. याचिकाकर्ता की ओर से उन्नत सामग्री का अंतिम भाग दो भागों में है। पहला भाग संबंधित है कार्यकाल की कटौती के कारण सामग्री की हानि से। इस तरह का नुकसान एक सेवा कैरियर में अज्ञात नहीं है और रोजगार की शर्तों में से एक है। कार्यकारी को पद का सृजन और उन्मूलन का विशेषाधिकार, और वर्तमान मामले में,राष्ट्रपति का अधिकार है। अनुच्छेद 324 (2) चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करता है। पोस्ट बनाने की शक्ति अनियंत्रित है।**

वैसे ही उन्हें कम करने या खत्म करने की शक्ति भी है। यदि ऐसा है तो, राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त का कोई काम न होने या उसका चुनाव आयोग का कार्य न कर पाने पर, पदों को समाप्त करने का निर्णय ले सकता है, जो याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित कार्यालय की एक अतिशयोक्त है। याचिका की निष्पक्षता में, हम यहां रिकॉर्ड कर सकते हैं कि श्री गोपाल सुब्रमणियम ने शुरू में इसे स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने अदालत से संपर्क अपने नुकसान की शिकायत के लिए नहीं लेकिन चुनाव आयोग की स्वतंत्रता क्या उसे पदों के उन्मूलन के उप-केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छेड़छाड़ करने की अनुमति के बारे में किया था। हमने इस पहलू को पहले काफी विस्तार से निपटाया है। "

(32) हमारी राय में, पूर्वोक्त अवलोकन पूरी तरह से विद्वान एडवोकेट जनरल, हरियाणा द्वारा किए गए सबमिशन का समर्थन करते हैं हमारे द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण कि अधिसूचना दिनांक 13 मई, 2005 पूरी तरह से कानूनी है और किसी भी कानूनी या न्यायसंगत से पीड़ित नहीं है।

(33) चूंकि कोई रिक्तियां नहीं हैं, इसलिए कोई मैन्डैमस जारी नहीं किया जा सकता है याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए। हमने पूरे चयन की प्रभावकारिता पर ध्यान दिया है और संदेह होने पर राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा जांच की गई है । इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण जो केवल चयन के लिए है कि नियुक्ति एक कानूनी अधिकार नहीं बनाता है जिसे मैन्डैमस की रिट से लागू किया जा सकता है। इस स्तर पर, हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों पर ध्यान दें,जो न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण और प्रस्तुतिकरण का समर्थन करें। हरियाणा राज्य *बनाम* सुभाष चंदर मरवाहा और अन्य *(*सुपरा*)* सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार देखा: –

"9. यह उच्च न्यायालय के तर्क का पालन करना मुश्किल है। यह इस बात से सहमत है कि 15 रिक्तियों के विज्ञापन ने किसी भी उम्मीदवार को अधिकार नहीं दिया। यह भी किसी तरह उम्मीदवार को एक अधिकार देने के लिए राजी किया क्योंकि वास्तव में 15 रिक्तियां थीं। पर एक जगह यह कहा गया था "जब तक की संख्या है

रिक्तियों को भरा जाना है और योग्य उम्मीदवार हैं लोक सेवा आयोग द्वारा अपने रोल्स के साथ अग्रेषित सूची में, उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त है भाग "सी" में नियम 10 (ii) के तहत"।

"10. कोई यह देखने में विफल रहता है कि रिक्तियों का अस्तित्व कैसे कानूनी है। परीक्षा यह दिखाने के उद्देश्य से है कि एक विशेष उम्मीदवार विचार के लिए पात्र है। चयन नियुक्ति बाद में आती है। यह तब सरकार के तय करना है कि कितनी नियुक्तियाँ की जाएंगी। मात्र तथ्य यह है कि सूची में एक उम्मीदवार का नाम दिखाई नहीं देगा उसे एक मंडमस के लिए हकदार है जिसे वह नियुक्त किया जाता है।

1 1. यह याद रखना चाहिए कि याचिका एक मंडामस के लिए है। इस न्यायालय ने डॉ. राय शिवेंद्र बहादुर *बनाम* नालंदा की शासी निकाय कॉलेज, के आदेश में बताया है कि मंडमस मजबूर करने के लिए जारी कर सकता है, यह दिखाया जाना चाहिए कि क़ानून उस अधिकार और कानूनी कर्तव्य को लागू करता है पीड़ित पार्टी को क़ानून के तहत कानूनी अधिकार प्राप्त है इसके प्रदर्शन को लागू करें। चूंकि सभी 15 व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार पर कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है, जो सूची में हैं और याचिककर्ता के पास याचिका को लागू करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इस नियम को स्पष्ट रूप से गलत समझा है।"

मणि सुब्रत जैन और अन्य *बनाम* राज्य का हरियाणा और अन्य (51), में सुप्रीम कोर्ट ने देखा है के तहत: –

"2. रिट याचिकाओं में अपीलकर्ताओं ने एक मंडमस के लिए कहा उत्तरदात्ता न. 1 और 2 को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्त करने के लिए। अपीलकर्ताओं ने मंडमस या कोई अन्य उपयुक्त रिट की मांग उत्तरदाता नं. 1 और 2 के आदेशों को खारिज करने के लिए की,जिससे उच्च न्यायालय को सूचित किया गया था कि सरकार अपीलकर्ताओं को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्त करने के लिए तैयार नहीं थी।

xxxxxx xxx

xxx

---

(51) (1977) 1 एस. सी. सी. 486

4. उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिकाओं को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ताओं के पास *लोक स्टैंडी* नहीं थी... उच्च न्यायालय द्वारा ने यह कारण दिया कि अपीलकर्ता नियुक्त नहीं किए और उन्हें नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें न नियुक्ति के बारे में जानने का अधिकार था।

9. उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को सही ठहराया। यह प्राथमिक है कि बहाल किया जाना है कि कोई भी पूछ नहीं सकता है एक कानूनी अधिकार के बिना एक मंडामस के लिए. एक होना चाहिए न्यायिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार के साथ-साथ कानूनी रूप से संरक्षित एक कानूनी शिकायत से पीड़ित होने से ठीक पहले एक के लिए पूछ सकते हैं। एक व्यक्ति को केवल तभी दुखी कहा जा सकता है जब किसी व्यक्ति के पास कानूनी अधिकार से वंचित किया जाता है कुछ करने या करने से रोकने के लिए कानूनी कर्तव्य कुछ कुछ. (इंग्लैंड के 4 वें एड के हल्सबरी के नियम देखें। वॉल्यूम. मैं, अनुच्छेद 122 ; हरियाणा राज्य *बनाम सुभाष* चंदर मारवाहा; जस्भाई मोतिभाई देसाई *बनाम* रोशन कुमार हाजी बशीर अहमद और फेरिस ; असाधारण कानूनी उपचार, अनुच्छेद 198)

जतिंदर कुमार और अन्य *बनाम* पंजाब राज्य
और अन्य *(सुपरा), मे* सुप्रीम कोर्ट ने देखा है: -

"10. अब हम श्री फ्रैंक एंथनी, अपीलकर्ताओं के वकील, कि द्वारा उठाए गए कंटेंट को लेते हैं जो यह कहते है कि उन्हें बोर्ड द्वारा किए गए चयन के आधार पर सहायक उप निरीक्षकों के पद पर नियुक्त होने का अधिकार है।

1 1. संविधान का अनुच्छेद 320 कर्तव्यों की गणना करता है संघ या राज्य लोक सेवा द्वारा प्रदर्शन किया गया आयोग:

(i) सेवाओं के लिए नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करना संघ और राज्य की सेवाओं के क्रमशः;

(ii) यदि ऐसा करने के लिए किसी भी दो या अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो संयुक्त राज्य की योजनाओं को तैयार करने और संचालित करने में वे राज्य किसी भी सेवा के लिए भर्ती के लिए विशेष योग्यता रखने की आवश्यकता है

(iii) अनुच्छेद के खंड (3) के तहत गणना किए गए मामलों पर सलाह देना 320 और

(iv) किसी भी मामले पर सलाह देने के लिए उन्हें और किसी अन्य को संदर्भित किया जाता है, मामला जो राष्ट्रपति या जैसा भी हो राज्य के राज्यपाल उन्हें संदर्भित कर सकते हैं।

तथ्य यह है कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि सलाह की स्वीकृति आयोग बनाता है, जब परामर्श किया जाता है, तो अनुच्छेद 320 (3) के प्रावधान केवल निर्देशिका और अनिवार्य प्रतिपादन करता है ।

12. जनता की तरह एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना सेवा आयोग सर्वोत्तम उपलब्ध का चयन सुनिश्चित करना है। मनमानी से बचने के लिए एक पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्ति और नियुक्ति के मामले में भाई-बहन का गठन किया जाता है। उच्च क्षमता, विविध अनुभव और व्यक्तियों द्वारा निर्विवाद अखंडता और विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्रदान की गई। यह सच है कि सरकार द्वारा वह नियुक्त किए जाते हैं लेकिन एक बार उन्हें नियुक्त करने कि स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से सुरक्षित है। जब भी सरकार की आवश्यकता होती है एक उच्च सार्वजनिक कार्यालय के लिए एक नियुक्ति करना आवश्यक है लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के लिए, तो चयन आयोग और सरकार द्वारा बनाया जाता है। चयनित लोगों को नियुक्त करके पदों को भरना है आदेश का पालन करने वाले आयोग द्वारा अनुशंसित लोक सेवा द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों की सूची में योग्यता आयोग द्वारा चयन किया जाता है, हालांकि, केवल आयोग और अंतिम की सिफारिश की नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास है। सरकार सिफारिश को स्वीकार कर सकती है या उसी को स्वीकार करने के लिए गिरावट कर सकती है। लेकिन अगर यह आयोग की संविधान की सिफारिश को स्वीकार नहीं करने का विकल्प चुनता है सरकार की मेज पर जगह बनाने के लिए संलग्न है, विधान सभा अपने कारणों और ऐसा करने के लिए रिपार्ट तैयार करती है। इस प्रकार, सरकार को सदन के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है किसी भी प्रस्थान के लिए, – संरक्षण के अनुच्छेद 323 पर निर्भर करता है। यह, हालांकि, अपीलकर्ताओं को किसी के साथ नहीं रखता है। वे सही के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं कि

सरकार को की सिफारिश को स्वीकार करना चाहिए आयोग। हालांकि, रिक्ति को भरना है, यूपी सरकार को नियुक्ति का सख्ती से पालन करना होगा। यह अन्य अच्छे कारणों को छोड़कर बुरा आचरण या चरित्र से खुद की मिठाई के लिए योग्यता के क्रम को परेशान नहीं कर सकता है। सरकार भी नहीं कर सकती एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जिसका नाम सूची में दिखाई नहीं देता है। लेकिन यह तय करना सरकार के लिए खुला है कि कितने नियुक्तियां की जाएंगी। चयन के लिए प्रक्रिया और प्रत्याशित के खिलाफ भर्ती के उद्देश्य के लिए चयन रिक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं बनता है जो पद मंडमस द्वारा लागू किया जा सकता है। सिल्वा *बनाम* भारत और संघ, हरियाणा का राज्य *बनाम* सुभाष चंदर मरवाहा पर हमने भरोसा किया है। इसके विपरीत श्री एंथनी के विवाद नहीं स्वीकार किए जाते हैं।"

शंकरन डैश *बनाम* भारत का संघ *(सुपरा)में,* सुप्रीम कोर्ट ने निम्न के रूप में देखा है: –

"7. यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति और पर्याप्त संख्या के लिए अधिसूचित उम्मीदवार फिट पाए जाते हैं, नियुक्त किया जाने वाला एक अनिश्चित अधिकार जो वैध रूप से नहीं हो सकता, उसे इनकार किया जाएगा। आमतौर पर अधिसूचना केवल योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए निमंत्रण देती है और उनके चयन पर वे पद का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। जब तक प्रासंगिक भर्ती नियम संकेत नहीं दें तो राज्य सभी को भरने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के पास मनमाने तरीके से अभिनय का लाइसेंस है। रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय लेना होगा *बोना फाइड* उचित कारणों के लिए है। और अगर रिक्तियां या कोई भी उनमें से भरे हुए हैं, राज्य सम्मान के लिए बाध्य है उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता, जैसा कि परिलक्षित होता है भर्ती परीक्षण, और किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस सही स्थिति का लगातार पालन किया गया है

कोर्ट, और हमें कोई भी अप्रिय नोट इन हरियाणा राज्य *बनाम* सुभाष चंदर मारवाहा, नीलिमा शांगला *बनाम* हरियाणा राज्य, या जतन्द्र कुमार *बनाम* पंजाब राज्य निर्णयो मे नहीं मिला।"

(36) सर्वोच्च न्यायालय का पूर्वोक्त हुक्म स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के पास मैंडेम की प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग करने के लिए बहुत कम या लागू करने योग्य कानूनी अधिकार नहीं है। श्री जसपाल सिंह, वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि पदों पर नियुक्तियां 2002 की धारा 4 के मद्देनजर विज्ञापित किया जाना होगा। हम इस विचार के हैं कि पूर्वोक्त प्रस्तुत पदार्थ के बिना है। 2002 का अधिनियम वास्तव में एम्बार्गो विज्ञापित पदों से परे नियुक्तियों पर करता है। यह कानूनी कर्तव्य नहीं है कि विज्ञापित सभी पदों पर नियुक्तियां करे। हम भी विद्वान के प्रॉमिसरी एस्टॉपल" की प्रस्तुतियों में ज्यादा पदार्थ नहीं पातें है । हमें इस पर संदेह है कि क्या "प्रॉमिसरी एस्टॉपल " 13 मई, 2005 की अधिसूचना का कार्यान्वयन के सिद्धांत के खिलाफ लागू होगे । दृश्य हमारा होगा सुप्रीम कोर्ट के ओ. एन. रमनथा पिल्लई *(सुपरा)*// पूर्वोक्त निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निम्नानुसार आयोजित किया है: –

"37. उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि कोई भी एस्टॉपल पद के उन्मूलन के संबंध में राज्य के खिलाफ नहीं उठ सकता है।अपीलकर्ता रामनाथा पिल्लई को पता था कि यह पद अस्थायी था।पृष्ठ 783 पर अमेरिकी न्यायशास्त्र 2 में अनुच्छेद 123, यह कहा गया है "आम तौर पर, राज्य पर एस्टोपेल एसे नहीं लगता जैसे वह एक व्यक्ति या एक निजी निगम पर होता है। अन्यथा, इसका प्रतिपादन किया जा सकता है सरकार अपनी शक्तियों का दावा करने के लिए असहाय है। इसलिए, एक सामान्य नियम के रूप में एस्टोपेल के सिद्धांत को लागू नहीं किया जाएगा अपनी सरकार, सार्वजनिक या संप्रभु में राज्य के खिलाफ क्षमता नहीं है। हालांकि, राज्य के लिए एस्टॉपल के आवेदन में एक अपवाद उत्पन्न होता है जहां इसे रोकना आवश्यक है धोखाधड़ी या प्रकट अन्याय " एस्टोपेल ने आरोप लगाया अपीलकर्ता रामनाथा पिल्लई इस आधार पर थे कि वह एक समझौते में प्रवेश किया और इस तरह उसका परिवर्तन हुआ। उच्च कोर्ट न्यायालयों के सिद्धांत के संचालन को बाहर करने मे ठीक है

एस्टोपेल, जब यह पाया जाता है कि प्राधिकरण किसके खिलाफ है एस्टॉपल को जनता के खिलाफ एक कर्तव्य माना जाता है जिसे एस्टॉपल काफी हद तक संचालित नहीं कर सकता है।"

(35) तथ्यों पर भी, याचिकाकर्ताओं को केवल चयन प्रक्रिया में दिखाने के लिए आमंत्रित किया था। इसमें कोई मजबूरी शामिल नहीं थी। आवेदन करने के किसी अन्य अवसर से वंचित नहीं था। इस तरह के एक तर्क को पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सशक्त रूप से खारिज कर दिया गया था। जतिंदर कुमार और अन्य *(सुपरा) में,* सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया: –

"16. हताशा का एक तर्क प्रॉमिसरी एस्टॉपल के बारे में उन्नत था, जो राज्य सरकार अपीलकर्ताओं की नियुक्ति न करने के कार्य को रोकने के लिए है हालाँकि उनके नामों की सिफारिश की गई थी। इस मामले में बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना केवल एक विशिष्ट योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को निमंत्रण कुछ पदों के लिए चयन के लिए आवेदन करना है। यह कोई वादा नहीं था कि चयन किया जाएगा या अगर यह बनाया गया था तो चयनित उम्मीदवार नियुक्त होंगे। उम्मीदवारों ने कोई अधिकार हासिल नहीं किया चयन के लिए या चयन के बाद नियुक्ति के लिए आवेदन करके। जब पंजाब सशस्त्र के विघटन का प्रस्ताव पुलिस बटालियन और इसके बजाय अतिरिक्त पदों का निर्माण राज्य द्वारा जिला पुलिस को ठुकरा दिया गया था, अपीलकर्ताओं को विधिवत स्थिति से अवगत कराया गया और राज्य के खिलाफ एस्टॉपल का कोई सवाल ही नहीं था ।"

(36) सर्वोच्च न्यायालय की पूर्वोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया गलत है। तथ्य में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ताओं ने आईएएस और अन्य की भर्ती के लिए आवेदन किया था । विद्वान वकील ने बताया कि 19 याचिकाकर्ता आईएएस के लिए उम्मीदवार थे।एक वास्तव में चयनित हो गया। इसके अलावा, 102में से 42 उम्मीदवार पहले से ही पहली कक्षा या द्वितीय मे काम कर रहे थे। हमारी राय में, पूर्वोक्त सबमिशन नींव पर हमला करता है। अब यह पेटेंट हो गया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी स्थिति को उनके अवरोध में नही बदल दिया, वे स्वतंत्र हैं

भविष्य की किसी भी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। वास्तव में, है पहले से ही अगले वर्ष के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया। इसलिए, यह संभव नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को कोई नुकसान हुआ हो नुकसान या क्षति, बहुत कम अपूरणीय क्षति, में भाग लेने से चयन प्रक्रिया।

(37) अब हम याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए विभिन्न निर्णयों को नोटिस कर सकते हैं।

(38) श्री जसपाल सिंह, वरिष्ठ वकील, पर भरोसा किया के मामले में किए गए सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित अवलोकन पी. महेंद्रन *(सुप्रा) :*

"1 1इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने अवलोकन किया कि

> केवल आवेदन करने से उम्मीदवार का अधिग्रहण नहीं होता है पोस्ट का कोई अधिकार। यह सच है कि एक उम्मीदवार केवल एक आवेदन करके पोस्ट का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है, लेकिन उसके पक्ष में एक अधिकार, शर्तों के अनुसार पद के लिए विचार किया गया और विज्ञापन की शर्तें और मौजूदा भर्ती नियम. से बनाया गया है।यदि कोई उम्मीदवार किसी पद के लिए आवेदन करता है लोक सेवा द्वारा जारी विज्ञापन की प्रतिक्रिया भर्ती नियमों के अनुसार आयोग चयन के अनुसार विचार करने का अधिकार प्राप्त करता है। यह अधिकार प्रभावित नहीं हो सकता किसी भी नियम के संशोधन द्वारा जब तक कि संशोधित नियम नहीं है।तत्काल मामले में, आयोग तत्कालीन मौजूदा नियमों के अनुसार काम किया था और कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता पात्र थे नियुक्ति, उनका चयन उल्लंघन में नहीं था । हमारी राय में ट्रिब्यूनल गलती में था आयोग द्वारा तैयार की गई चुनिंदा सूची को अलग करने में। "

(39) हमारी राय है कि पूर्वोक्त अवलोकन करते हैं किसी भी तरीके से याचिकाकर्ताओं के दावे का समर्थन नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि एक उम्मीदवार केवल आवेदन करके पोस्ट का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है। वह केवल अधिकार प्राप्त तत्कालीन मौजूदा नियमों के अनुसार चयन के लिए विचार किया जाना है। हमारी राय में, 13 मई, 2005 की अधिसूचना किसी भी संशोधन के बारे में नहीं लाई गई है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के किसी भी निहित अधिकार को हटाने का सवाल ही नहीं उठता।

(40) इसके बाद, श्री जसपाल सिंह निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर निर्भर थे। टी। डेविन कट्टी *(सुप्रा) :–*

> "1 1. प्रश्न का एक और पहलू अभी तक है। कहाँ विज्ञापन सीधे के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए जारी किया जाता है पदों की श्रेणी में भर्ती, और विज्ञापन स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चयन के अनुसार किया जाएगा मौजूदा नियमों या सरकारी आदेशों के साथ, और यदि यह आगे के पक्ष में आरक्षण की सीमा को इंगित करता है विभिन्न श्रेणियों, ऐसे मामले में उम्मीदवारों का चयन तत्कालीन मौजूदा के अनुसार किया जाना चाहिए। जो उम्मीदवार आवेदन करते हैं, और लिखित या से गुजरते हैं *चिरायु आवाज* परीक्षण के लिए निहित अधिकार प्राप्त है शर्तों के अनुसार चयन के लिए विचार किया जा रहा है और विज्ञापन में निहित शर्तें, जब तक कि विज्ञापन स्वयं संकेत देता है ।आम तौर पर, एक उम्मीदवार को विचार करने का अधिकार होता है में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार की तारीख पर उनके सही क्रिस्टलीकरण के रूप में विज्ञापन विज्ञापन पर प्रकाशन, हालांकि, उसके पास कोई पूर्ण नहीं है।"

(41) हमारी राय में, के तथ्यों और परिस्थितियों में वर्तमान मामला, इन टिप्पणियों से याचिकाकर्ता की कोई सहायता नहीं होगी। जैसा कि पहले देखा गया है कि किसी में कोई नियम संशोधन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का एक खंडन ऊपर दिए गए पुनरुत्पादन से पता चलता है कि उम्मीदवारों का चयन मौजूदा नियमों के अनुसार किया जाना है। ये अवलोकन रिक्तियों के आरक्षण के संदर्भ में बनाया गया है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो उम्मीदवार लिखित या चिरायु से गुजरते हैं परीक्षण के अनुसार चयन के लिए विचार किए जाने के लिए निहित अधिकार प्राप्त है विज्ञापन में निहित नियमों और शर्तों के साथ, जब तक कि विज्ञापन स्वयं एक विपरीत इरादे को इंगित करता है। विज्ञापन दिनांक 24 जनवरी, 2004 स्पष्ट रूप से नोट (i) में प्रदान किया गया प्रत्येक श्रेणी के विरुद्ध दिए गए पदों की संख्या भिन्नता के लिए उत्तरदायी है।" यह खंड स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि कोई भी उम्मीदवार किसी विशेष पर चुने जाने के लिए किसी भी निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।खण्ड किसी भी तरह के पदों में भिन्नता की अनुमति देता है। यह विद्वान सीनियर का स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है। वकील

वचन के आधार पर प्रस्तुतियाँ के समर्थन में विज्ञापन में एस्टॉपल पर सभी याचिकाकर्ताओं ने नियम और शर्तों पर भरोसा किया था । याचिकाकर्ताओं को चुनिंदा हिस्सों पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है विज्ञापन के, उनके दावे के समर्थन में। यदि उन्हें शर्तों के अनुसार चयन के लिए विचार करने का अधिकार है और विज्ञापन में निर्धारित की गई शर्तें, जैसा कि उनके लिए क्रिस्टल है विज्ञापन का प्रकाशन, एक दायित्व भी विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख पर क्रिस्टलाइज्ड करना चाहता है ,रिक्तियोंके लिए नहीं चुना जाना चाहिए। यह हमारी राय में, इसका स्वाभाविक अर्थ होगा नोट (1) में निहित क्लॉज को दिया जाए जो उस नंबर को प्रदान करता है प्रत्येक श्रेणी के विरुद्ध दिए गए पद किसी भी सीमा तक भिन्नता के लिए उत्तरदायी हैं । शब्द "एक्सटेंट" को भारतीय संस्करण में परिभाषित किया गया है वेबस्टर के न्यू कॉलेजिएट डिक्शनरी के 1981 संस्करण में प्रकाशित 1983, इस प्रकार है: –

"अतिशयोक्ति

1. XXX XXXXXX XXX

2. XXX XXXXXX XXX

3. ए : वह सीमा जिस पर कुछ फैलता है: गुंजाइश < उनके अधिकार की सीमा > बी : बिंदु डिग्री, या करने के लिए सीमा जो कुछ स्तन तक प्रतिभा का उपयोग करके < का विस्तार करता है हद. सी : अंतरिक्ष या सतह की मात्रा जो किसी चीज पर कब्जा कर लेती है या जिस दूरी पर उसका विस्तार होता है: परिमाण (जंगल की सीमा)। "

(42) पूर्वोक्त परिभाषा स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि याचिकाकर्ता किसी निश्चित पर नियुक्त किए जाने के किसी भी कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकते । यह, हमारी राय में, स्पष्ट रूप से आयोजित किया गया है मामले में दिए गए फैसले के पैरा 11 में सुप्रीम कोर्ट का एन. टी डेविन कट्टी *(सुपरा)* जिसमें आरक्षण की सीमा है 6 सितंबर, 1969 को विचाराधीन चयन के लिए तय किया गया था।

(43) श्री जसपाल सिंह सीनियर वकील का तर्क सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित लघु आदेश भीम सिंह *(सुपरा)*, प्रॉमिसरी एस्टॉपल पर उनकी अधीनता के समर्थन मे है।निर्णय इस प्रकार है: –

"1. छोड़ दिया गया।

2. दोनों पक्षों के वकील को सुनने के बाद, हम इसका निपटान करते हैं अपील के रूप में इसमें पहले से ही कानून का एकान्त बिंदु शामिल है इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा कवर किया गया है।

3. पूर्व के आधार पर। पी 1, राज्य (प्रतिवादी) कुछ निश्चित है अपीलकर्ताओं के लिए एक संकेत के रूप में विशिष्ट वादे एक नए विभाग (कृषि विभाग) में कदम रखें. कृषि विभाग, राज्य, अपने पूर्व के आधार पर चले जाने के बाद। पी 3, वापस जाने की मांग की पूर्व में किया गया वादा। पी 1. अपीलकर्ता राज्य द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व और होने पर विश्वास किया आगे की कार्यवाही अब उनकी आशाओं को पराजित नहीं कर सकती है जो अधिकारों में क्रिस्टलीकृत हो गए हैं, प्रॉमिसरी एस्टॉपल के सिद्धांत का अनुप्रयोग। इसलिए, यह कानून के अनुसार, राज्य के लिए खुला नहीं है इस न्यायालय द्वारा, पीछे हटने के लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए, हम प्रत्यक्ष पूर्व को लागू करने के लिए राज्य पी -1 और ऐसे अधिकारों को प्रदान करता है तथा लाभ के रूप में वादा किया जाता है। श्री बी. दत्त कहते हैं कि थोड़ा समय के लिए आवश्यक हो सकता है विभिन्न विभागों को फिर से पढ़ने के लिए, हम तीन महीने की अनुमति देते हैं पूर्व के कार्यान्वयन के लिए समय भी देते है। पी -1, असफल जो राज्य ब्रीच में आयोजित किया जाएगा। कोई लागत नहीं।"

(44) यह पूर्वोक्त टिप्पणियों से प्रकट होता है कि प्रतिवादी – राज्य ने एक नया विभाग बनाया था। कुछ कर्मचारी प्रतिवादी – राज्य को नए में शामिल होने के लिए राजी किया गया था, अतिरिक्त विभाग के कुछ वादे करने के बाद कर्मचारी नए विभाग में शामिल हो गए, लाभ मांगे गए वापस लिया जाना। ऐसी परिस्थितियों में, एक दिशा जारी की गई थी ऐसे अधिकारों और लाभों को प्रदान करने के लिए राज्य जो पहले वादा किया गया था. वर्तमान मामले में, कोई वादा नहीं किया गया था। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पदों की संख्या भिन्नता के अधीन है।

(45) श्री जसपाल सिंह ने तब एक डिवीजन बेंच में दिल्ली उच्च न्यायालय की कनिष्क अग्रवाल *(सुपरा)*। मंडल बेंच, इस मामले में, छात्रों के अधिकारों को जारी रखने पर विचार कर रही थी एलएलबी पाठ्यक्रम में जिसमें उन्हें भर्ती कराया गया था। यह हालांकि, विश्वविद्यालय द्वारा दावा किया गया कि छात्र अनियमित रूप से अनंतिम प्रवेश दिया था।इसलिए, उनके प्रवेश की पुष्टि नही की थी। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इसमें शामिल होने की अनुमति दी थी, कक्षाएं और 1 सेमेस्टर परीक्षा के लिए बैठना। यह आदेश 13 दिसंबर, 1990 को पारित हुआथा। निर्णय 11 तारीख को दिया गया था।

मार्च, 1991. श्री शांति भूषण, के लिए उपस्थित वकील ने चार आधारों के उल्लंघन पर राहत मांगी थी(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15; (ii) याचिकाकर्ता प्रवेश समिति के नियम के बारे में सूचित नहीं किया गया था; (iii) विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई कार्यवाही करने से रोक दिया गया था; (iv) चूंकि याचिकाकर्ता ने किसी भी जानकारी को दबाया नहीं था और उसने अपेक्षित प्रवेश पत्र जमा किया था; उसने प्रवेश शुल्क जमा किया था; कक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, यह खुला नहीं था विश्वविद्यालय अब पूर्ववत करने के लिए जो पहले से ही किया गया था। ध्यान में रखते हुए बेंच, जसपाल के लिए बोलते हुए, 'प्रॉमिसरी एस्टॉपल ' की दलील सिंह, जे। निम्नानुसार मनाया गया: –

"30. हमें लगता है, सम्मान के साथ, कि श्री राव मांग रहे थे, उन्नीसवीं सदी के बाद के आधे हिस्से को फिर से लागू करने के लिए पहले से ही समान एस्टॉपल को तबाह होते देखा था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जॉर्डन *बनाम* पैसे (1854) 10 ईआर प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिनिधित्व द्वारा 868 एस्टोपेल को सीमित करना मौजूदा तथ्य और फिर विलमॉट में फ्राई जे द्वारा *बनाम* बारबेट (१ ((०) १५ च डी ९ ० जिसने एक श्रृंखला रखी प्रोबांडा (हमें आभास हुआ, हम गलत तरीके से चाहते हैं, जैसे कि iff श्री राव प्रोबांडा को चैंपियन बना रहे थे) और बोउन द्वारा में एल.जे कम *बनाम बुवेयरे* (1891) 3 Ch 82 दयापूर्वक केवल रैमस्डेन *बनाम* डायसन (१ (६६) आईआर १ एचएल १२ ९ हो सकता है उन्नीसवीं सदी के बीहड़ों से बचो, हालांकि यह बुरी तरह से चोट लगने से बच नहीं सकता था. यह मोटे तौर पर था अधिग्रहण द्वारा एस्टोपेल के क्षेत्र को कवर किया गया. यह चोट लगी थी जैसा कि यह योग्यता के अधीन हो गया था विलमॉट में फ्राई जे का प्रोबांडा और होने तक सीमित है साक्ष्य का एक नियम. इसे इसके मध्य वर्षों तक छोड़ दिया गया था लागू किए गए झोंपड़ियों को तोड़ने के लिए सदी रैमस्डेन *बनाम* डायसन (1866-LR 1 HL 129) सिद्धांत द्वारा इसे अब हम "मालिकाना" कहते हैं एस्टॉपल". यह फ्राई जे के प्रोबांडा द्वारा सीमित नहीं है. (देख शॉ *बनाम* Applegate (1977) 1 डब्ल्यूएलआर 970; टेलर फैशन लिमिटेड. *बनाम* लिवरपूल विक्टोरिया ट्रस्टी सह, लिमिटेड. (1982) 1 QB 133 : समामेलित निवेश और संपत्ति कंपनी. लिमिटेड. *बनाम* टेक्सास वाणिज्य अंतर्राष्ट्रीय बैंक (1982) 1 क्यूबी 84); यह के रूप में काम कर सकते हैं कार्यवाही का एक कारण, (देखें : समामेलित निवेश, *(Ibid)* यह सामान्य प्रयोज्यता का है (देखें मूरगेट मर्कैंटिटेल

बनाम टिवीचिंग (1976) QB 225; पश्चिमी मछली उत्पाद लिमिटेड. *बनाम* पेनविथ जिला परिषद (1981) 2 सभी ईआर 204, 208; हबीब बैंक लि. *बनाम* हबीब बैंक एजी ज्यूरिख (1981) 1 डब्ल्यूएलआर 1265, 1282), और सबसे ऊपर यह वर्गीकरण के अधीन नहीं (देखें क्रैब *बनाम* अरुण जिला परिषद (1975-3 सभी ईआर 865). इसका स्वागत किया गया है "एक सामान्य सिद्धांत सीमा के अनुसार" (प्रति भगवान डेन्निंग सी अमलगमेटेड इन्वेस्टमेंट *सुप्रा)* और के रूप में एक सबसे "सामान्य", "लचीला" और "उपयोगी सिद्धांत" *(Ibid)*। हम इस स्तर पर, उस महान न्यायाधीश के आने का भी उल्लेख कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से – डिक्सन जे।, और अपने दो निर्णयों के लिए थॉम्पसन *बनाम* पामर और ग्रुंड *बनाम* महान बिल्डर्स पीटीआई. गोल्ड माइन्स लि. (1937) 59 सीएलआर 641. क्या हमारे उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है कि बाद के निर्णय में डिक्सन जे ने पेस में अपने एस्टोपेल के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में लिया, पार्टी द्वारा स्थापित "धारणा" की स्थापना की गई पार्टी के आचरण के बजाय एस्टोपेल की मांग की गई। "एक एस्टोपेल को जन्म देने वाले आचरण" के रूप" जिसे डिक्सन जे ने पामर में संदर्भित किया *बनाम* थॉम्पसन *(सुपरा)* "कन्वेंशन द्वारा एस्टोपेल" के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है", अधिकारों के प्रयोग से एस्टोपेल "," अधिग्रहण द्वारा रोक दिया गया दूसरे की गलती में "," लापरवाही से रोक "और "प्रतिनिधित्व द्वारा रोक". वादे करने की धारणा का इनमें से किसी में कोई स्थान नहीं है।

31. हालाँकि, श्री राव चाहते थे कि हम बहुत भारी ओनस याचिकाकर्ता पर लगाएं और हालांकि, उनके अनुसार, विश्वविद्यालय की ओर से आचरण को दिखाया जाना चाहिए था स्पष्ट, बिना त्रुटि के और अभिनिर्धारित (एक ही जा रहा है, उसके अनुसार, याचिका को संतुष्ट करने के लिए केंद्रीय) एस्टोपेल की आवश्यकता और यद्यपि वह भी चाहते थे कि हम यह मानें कि प्रतिनिधित्व व्यक्त किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता, कानूनी रूप से कार्य करने के लिए अग्रणी स्थिति अब इस प्रकार प्रतीत होती है: (i) पार्टी पर एस्टोपेल का ओनस बहुत हल्का है ; (ii) कोई एक्सप्रेस प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है; (iii) प्रतिनिधित्व फार्म भौतिक नहीं है, एक मात्र उठाना एक अपेक्षा पर्याप्त होगी; (iv) परिचित या खड़े होकर पर्याप्त होगा [प्रति लॉर्ड किंग्सडोम में रामसेन (1866 LR 1 HL 129), *सुप्रा]; (V)* बहुत न्यूनतम आचरण की आवश्यकता होती है।

(46) यहां तक कि पूर्वोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं को वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई राहत दी जा सकती है। जैसा कि पहले देखा गया था 24 जनवरी, 2004 का विज्ञापन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि भरे जाने वाले पदों की संख्या किसी भी सीमा तक भिन्नता के अधीन है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी में निहित "भिन्नता" शब्द की परिभाषा शब्दकोश *(सुपरा)* इंगित करता है कि यह परिवर्तन की विशेषता शुद्धता या कठोरता के बजाय क्षमता को दर्शाता है। इसके तहत नोट में वास्तविक शब्द विचार यह है कि पद किसी भी हद तक परिवर्तनशील हैं। वेबस्टर के न्यू कॉलेजिएट में निहित "एक्सटेंट" शब्द की परिभाषा शब्दकोश *(सुपरा)* स्पष्ट रूप से पता चलता है कि "विस्तार" शब्द को निरूपित कर सकता है। इस प्रकार, "किसी भी सीमा" शब्द किसी भी सीमा तक कई पदों में भिन्नता की अनुमति देगा। वर्तमान मामले में, कैडर की ताकत रही है याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए 300 पदों के विपरीत 230 पर तय किया गया। इसलिए, इसे शायद ही एक भिन्नता कहा जा सकता है हद या काफी हद तक। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं को नुकसान या कोई अपूरणीय क्षति नहीं हुआ है। वर्तमान मामले में, वचन का दावा एस्टोपेल सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ होगा जतिंदर कुमार (सुप्रा) के मामले में, हम यह भी देख सकते हैं कि यह प्रॉमिसरी एस्टोपेल पर तर्क विद्वान द्वारा उठाया गया है। "प्रॉमिसरी एस्टोपेल" कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न होगा। इसलिए, इसे ठीक से निवेदन करना होगा और साबित करना होगा। हमारी राय में, "प्रॉमिसरी एस्टोपेल" की कोई दलील नहीं दी जा सकती है, जब तक यह निवेदन नहीं किया जाता है और इसके लिए तथ्यात्मक नींव रखी जाती है। हमारे इस दृष्टिकोण को टिप्पणियों मिस मोटिलाल पडंपट शुगर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का मिल्स कंपनी. लिमिटेड. *(सुपरा)*से समर्थन मिलेगा। जिसमें इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया है

> "5...यह प्राथमिक है कि छूट तथ्य का सवाल है और
>
> इसे ठीक से निवेदन और सिद्ध किया जाना चाहिए। छूट की कोई दलील नहीं जब तक यह निवेदन नहीं किया जाता है तब तक इसे उठाया जा सकता है इसके लिए तथ्यात्मक नींव रखी गई है।"

(47) कनिष्क अग्रवाल के मामले में डिवीजन बेंच *(सुपरा)* छात्रों के दावे पर विचार कर रहा था, जिसका पूरा भविष्य जैसा कि कानून के छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा खतरे में डाल दिया गया था, जब यह अनंतिम प्रवेश की पुष्टि करने से इनकार कर दिया गया था जो उन्हे प्रदान किया गया था। अध्ययन के एक वर्ष का नुकसान निश्चित रूप से छात्रों को अपूरणीय क्षति से हुआ होगा।वे किसी भी तरह से दोषी ठहराया नहीं गया। इसलिए डिवीजन बेंच उनके बचाव में आया और अनुमति दी गई उन्हें पाठ्यक्रम में जारी रखने के लिए। वर्तमान मामले में, कोई राहत नहीं हो सकती है "प्रॉमिसरी एस्टोपेल" के सिद्धांत पर याचिकाकर्ताओं को दी गई"

(48) इससे पहले कि हम श्री चत्रथ द्वारा उद्धृत निर्णयों पर विचार करें, हम देख सकते हैं कि के शुरू होने पर तर्क, अपनी सामान्य तेजतर्रार शैली में, उन्होंने कहा था कि " पिछली सरकार के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त न करना सामान्य है हरियाणा के अभ्यास में"।हम इस तरह के व्यापक बयान का न्यायिक नोटिस नहीं ले पाएंगे ।

(49) अब हम श्री जी.के. चतुरथ के दिए गए निर्णयों पर विचार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश *बनाम शिंघारा* सिंह *(सुपरा),में* सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि जहां एक निश्चित तरीके से एक निश्चित कार्य करने के लिए एक शक्ति दी जाती है, उस चीज को उस तरह से किया जाना चाहिए और न सी उनसे, जिन्हें प्रदर्शन के अन्य तरीकों को आवश्यक रूप से मना किया गया है। हुकुम चंद श्याम लाल *(सुपरा)* तथा चंद्र किशोर झा *(सुपरा),* में कानून निर्धारित किया गया है शिंघारा सिंह *(सुपरा)* दोहराया गया है। एम. एस. एहलावत *(सुपरा)* से संबंधित है धारा 195 और 340 Cr.P.C के प्रावधानों की व्याख्या। यह माना गया है कि लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया इसमें उल्लिखित किसी भी अपराध का संज्ञान अनिवार्य है। निर्णय के पहले भाग में, हमने यह माना है कि उत्तरदाताओं ने जारी करने से पहले वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है अधिसूचना दिनांक 13 मई, 2005. इसलिए, नियम निर्धारित किया गया इन निर्णयों में उल्लंघन नहीं किया गया है। राज कुमारी *(सुपरा),* नियुक्ति के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थीं पंजाब राज्य द्वारा नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया था। नियुक्ति आदेश पहले ही जारी किया जा चुका था। याचिकाकर्ता को शामिल होने की अनुमति नहीं दी, इस तथ्य के बावजूद कि वह अनुसूचित थी। इसलिए, मामले के अजीब तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच, जिसमें से हम में एस. एस. निज्जर, जे।) एक सदस्य थे, उत्तरदाताओं को अनुमति देने और शामिल होने के लिए निर्देशित किया। पूर्वोक्त निर्णय से याचिकाकर्ताओं के लिए कोई फायदा नहीं है। हमारा यह भी मत है कि इस संबंध में प्रस्तुतियाँ सतर्कता जांच की पेंडेंसी या अन्यथा, कोई परिणाम नहीं है। याचिकाकर्ताओं को जमीन पर नियुक्तियों से वंचित नहीं किया गया है उनका चयन दागी होने के लिए किया गया था। उत्तरदाता ने रिक्तियों की इच्छा के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने में असमर्थता दिखाई। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन इंदरप्रीत सिंह कहलोन और अन्य *बनाम* पंजाब राज्य और अन्य *(सुपरा)* में याचिकाकर्ताओं की कोई सहायता नहीं होगी

वर्तमान मामला। इसमें पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) और साथ ही पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा)में नियुक्तियां की गई थीं। अधिकारियों ने काफी समय तक काम किया था। हालांकि, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के व्यापक आरोपों के कारण पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ तथ्य खोजने के आधार पर नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था इस न्यायालय की दो उप-समितियों की जाँच, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में समाप्त किया गया और भारत के संविधान का अनुच्छेद 311 लागू किया गया। जैसा कि पहले देखा गया था, याचिकाकर्ता द्वारा कई वर्षों से काम किया जा रहा था। उनमें से कुछ के पास यहां तक कि परिवीक्षा की अवधि को भी मंजूरी थी। हमारी राय में, टिप्पणियों पूर्वोक्त तथ्यों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होना चाहिए। इंदरप्रीत सिंह कहलोन मेे, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि: –

> "54. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि एक निर्णय के लिए एक प्राधिकरण है यह तय करता है किसमे तार्किक रूप से कटौती नहीं की जा सकती है। यह भी अच्छी तरह से तय है कि मामले का अनुपात होना चाहिए तथ्य प्राप्त करने की स्थिति के संबंध में समझा जा सकता है। [देख पी. एस. सैथप्पन (मृत) एल द्वारा *बनाम* आंध्र बैंक लिमिटेड और अन्य, एम.पी. गोपालाकृष्णा नायर *बनाम* केरला राज्य और हरियाणा राज्य कॉप. भूमि विकास बैंक *बनाम* नीलम]."

(50) सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से सामने आती हैं नीचे कि निर्णय के अनुपात को समझा जाना चाहिए,वह भी तथ्य के संबंध में। वर्तमान के तथ्य, मामला के तथ्यों से पूरी तरह अलग है जो इसके तहत थे कि सर्वोच्च न्यायालय का इंद्रप्रीत सिंह काहलोन और अन्य *बनाम* पंजाब राज्य और अन्य था । वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है। सतर्कता जांच की पेंडेंसी केवल निर्णय के लिए एक अतिरिक्त औचित्य के रूप में दिया गया।

(51) हमें श्री राजीव अत्मा राम द्वारा निर्मित, सबमिशन में ज्यादा पदार्थ नहीं मिलते हैं। मॉडल कोड के खंड 7 (vi) (डी) के तहत प्रतिबंध नियुक्ति केवल तदर्थ नियुक्ति तक ही सीमित है। वहां हो सकता है नियमित नियुक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वैध चयनों के अनुसार एचपीएससी द्वारा बनाया गया। हमारी राय में, विद्वान की प्रस्तुतियाँ

डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए दृश्य के लिए वकील रन काउंटर हरबन्स सिंह जलाल, पूर्व, विधायक, बठिंडा *(सुपरा)* पर किया ।इस मामले में, यह स्पष्ट रूप से आयोजित किया गया है कि चुनाव आयोग हकदार था, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे । डिवीजन बेंच की प्रासंगिक टिप्पणियों को पुन: पेश कर सकते है :-

> "24. ऊपर जो कहा गया है, उसे देखते हुए हम स्पष्ट ध्यान रखें कि चुनाव आयोग लेने का हकदार है चुनाव की घोषणा की तारीख से अधिसूचना जारी करने की तारीख के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए आवश्यक कदम, जो ऐसा करते समय, सभी के द्वारा अपनाई जाने वाली आचार संहिता राजनीतिक दल सहित राजनीतिक दल सरकार, चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। इस संबंध में आयोग की कार्यवाही नहीं हो सकती दकि अपनाई गई उक्त मॉडल आचार संहिता दोषपूर्ण है, राजनीतिक दल किसी भी वैधानिक के खिलाफ नहीं जाते हैं। यह केवल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन सुनिश्चित करता है जो शुद्ध होना चाहिए। "

(52) उपरोक्त अर्क से, यह स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव सभी आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए आयोग चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष आचरण के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में था। यह भी देख सकते हैं 23 दिसंबर, 2004 और 27 दिसंबर, 2004 के पत्र से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किसी भी घटना में पूरी तरह से अप्रभावी रहे। यह रिकॉर्ड की बात है 27 फरवरी, 2005 को वोटों की गिनती होनी थी। विधानसभा चुनावों के बाद, वर्तमान सरकार सत्ता में आई। अन्यथा भी, केवल दिशाएं 23 दिसंबर, 2004 और 27 दिसंबर के पत्रों में जारी किए गए, 2004 की अनुमति के बिना, नियुक्तियां करना नहीं था जब तक मॉडल आचार संहिता ऑपरेशन में है। इसलिए, पूर्वोक्त पत्र दिनांक 23 दिसंबर, 2004 और 27 दिसंबर, 2004 को पूर्ण रूप से अवतार नहीं लिया गया। भले ही पूर्वोक्त दो पत्रों को नजरअंदाज किया जाना था, फिर भी रिक्तियों के लिए राहत नहीं दी जा सकती थी।

(53) अब हम उन निर्णयों पर विचार कर सकते हैं जिन पर श्री राजीव अत्मा राम, सीनियर, द्वारा भरोसा किया गया था। बबीता गुप्ता *(सुपरा),* याचिकाकर्ता को नियुक्ति के साथ-साथ जारी किया गया था पोस्टिंग का आदेश। इसलिए, डीपीआई (स्कूल), पंजाब को निर्देशित किया गया था सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखित निर्देश जारी करें और अन्य सक्षम अधिकारियों को चयनित और विधिवत नियुक्त करने की अनुमति

शिक्षक अपने कर्तव्य में शामिल होने के लिए। वर्तमान मामले में, न तो कोई रिक्ति मौजूद है और न ही कोई नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। इसलिए, बबीता गुप्ता *(सुपरा) मे* याचिकाकर्ताओं को सहायता नहीं है। जे. दिवाकर *(सुपरा),* ए राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे मे विज्ञापित पद था। उसमें अपीलकर्ताओं ने पद के लिए आवेदन किया था। तथापि, चयन सूची को अंतिम रूप दिए जाने से पहले, पोस्ट को वापस ले लिया गया था। सरकार ने नियमित किया सभी अस्थायी सरकारी सेवकों की सेवाएं, जिन्हें विज्ञापित पदों सहित किसी भी श्रेणी के पद पर सीधे भर्ती से नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किया अपने आप में उम्मीदवार के लिए पद का कोई अधिकार नहीं बनाता है, जो, विज्ञापन के जवाब में, एक आवेदन करता है। यह माना कि अपीलकर्ताओं को सरकार को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि, न्यायालय, के बीच न्याय करने के लिए पार्टियों ने आयोग को आधार पर चयन सूची को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया का *चिरायु आवाज* परीक्षण किया गया और सरकार को उसी को सौंपा और अग्रेषित किया गया। यह आगे निर्देशित किया गया था कि यदि अपीलकर्ता या उनमें से कोई भी चयन के क्षेत्र में आता है, उन्हें पहले होना चाहिए किसी भी बाहरी व्यक्ति से पहले चयन सूची में उनके स्थान के अनुसार नियुक्त किया गया पद पर नियुक्त किया जाता है। इन टिप्पणियों से कोई सहायता नहीं मिलती है , जैसा कि वर्तमान मामले में है, न तो कोई रिक्ति मौजूद है, न ही कोई अन्य व्यक्तियों को उन पदों पर नियुक्त किया गया है जो विज्ञापित किए गए थे। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है बसे कानून कि चुनिंदा पैनल के किसी व्यक्ति को कोई निहित अधिकार नहीं है उस पद पर नियुक्त किया जाए जिसके लिए उसे चुना गया है। उसका अधिकार है नियुक्ति के लिए विचार किया जाना है, लेकिन एक ही समय में, नियुक्ति प्राधिकरण चयन पैनल को अनदेखा नहीं कर सकता या बनाने के लिए गिरावट नहीं कर सकता। यह भी देखा गया है कि जब एक व्यक्ति को चयन बोर्ड द्वारा चुना गया है और एक रिक्ति है जो उसे उसकी योग्यता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पेश किया जा सकता है आमतौर पर, नियुक्ति के लिए उसे अनदेखा करने का कोई औचित्य नहीं है। एक व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए गिरावट का उचित कारण होना चाहिए। उस मामले के तथ्यों पर, सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इस पर केवल एक निष्क्रियता रही है। कोई कारण नहीं बताया गया था एक उम्मीदवार को नियुक्तियों की पेशकश क्यों कानून के अनुसार नहीं की गई। ये अवलोकन लागू नहीं होंगे वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में। सरकार नियुक्तियां नहीं करने के लिए एक सचेत निर्णय लिया है कोई रिक्तियां जिस पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए,

किसी भी चयन सूची का पालन करने का कोई सवाल ही नहीं है। राघव राजगोपालाचारी *(सुपरा)* मे सुप्रीम कोर्ट ने सलामी दी कि एक रिट याचिका के उत्तरदाता को अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह एक प्रतिवादी के रूप में अपने स्वयं के आदेश पर हमला करें। यह सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं है। उत्तरदाताओं द्वारा पारित किसी भी पहले के आदेश पर हमला नहीं कर रहे हैं। वे केवल कुछ प्रचार पदों पर कब्जा कर रहे हैं प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए और यह कि प्रचार अधिक से अधिक हैं। जोगिंदर पाल सिंह *(सुपरा),* एक एकल न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय ने कानून के शासन का पालन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने रघव राजगोपालचारी *(सुपरा) और* पंजाब पर्यटन विकास निगम *(सुपरा),*मे प्रबंधन ने श्रम द्वारा पारित पुरस्कार को चुनौती दी थी न्यायालय जिसके तहत काम करने वालों को सेवा में बहाल किया गया था। लेबर कोर्ट ने औद्योगिक की धारा 11-ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया था इस न्यायालय ने माना कि श्रम न्यायालय का पुरस्कार कानून के अनुसार पारित किया गया था । यह माना गया कि श्रम न्यायालय द्वारा दी गई सजा करने का अधिकार क्षेत्र था। यह माना गया कि श्रम न्यायालय द्वारा दी गई सजा के मुद्दे की जांच करने के लिए एक कर्तव्य के तहत है कि क्या सजा उचित है या नहीं। आगे यह माना गया कि ट्रिब्यूनल या लेबर के मामले में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सजा अनुचित है या कदाचार के लिए अत्यधिक अनुपातहीन साबित है, श्रम कोर्ट / ट्रिब्यूनल सजा के पुरस्कार में हस्तक्षेप कर सकता है। डिवीजन बेंच ने भी अच्छी तरह से बसे सिद्धांत को दोहराया भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सर्टिफिकेट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना इस न्यायालय के पुरस्कार में हस्तक्षेप कर सकता है श्रम न्यायालय केवल अगर यह अधिकार क्षेत्र या इसके विपरीत दिखाया जाता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के लिए या यह स्थापित किया जाता है कि लगाया गया पुरस्कार कानून की एक त्रुटि से ग्रस्त है जो इसके चेहरे पर स्पष्ट है। हम यह देखने में विफल हैं कि ये टिप्पणियां याचिकाकर्ताओं को कैसे सहायतित है। सुखदेव सिंह सिद्धू *(सुपरा),* मे इस न्यायालय की एक पूर्ण बेंच थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा की चयन प्रक्रिया पर कैट द्वारा जारी अंतरिम आदेश पर विचार किया । यह माना गया कि ट्रिब्यूनल की आवश्यकता है न केवल पार्टियों के हित पर विचार करें, बल्कि बड़े हित भी किसी भी अंतरिम से पहले सार्वजनिक हित के तत्व के रूप में सेवा राज्य को पदोन्नति देने से रोकने के आदेश जारी किए जाते है। ये टिप्पणियां, हमारी राय में, किसी भी तरह की मान्यता नहीं हैं। गिरिश अरोड़ा *(सुपरा),* डिवीजन बेंच के मामले में निर्धारित कानून कथा दोहराया है, जो कि शंकरन डैश

(सुपरा) मनमाने ढंग से सरकार नियुक्तियां करने से इनकार नहीं कर सकती । यह पहले से ही हमारे द्वारा आयोजित किया गया है कि कार्यवाही न तो अनुचित है और न ही मनमानी है ।

(54) श्री आर.के. मलिक द्वारा उद्धृत निर्णय पर ध्यान दिया जा सकता है। प्रेम चंदर, नायब तहसीलर (सुप्रा), एक डिवीजन बेंच का मामला इस न्यायालय ने माना कि किसी पद को समाप्त करने की कार्यकारिणी की शक्ति रही है। लेकिन इसे हमेशा अच्छे विश्वास और सार्वजनिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए ब्याज और कभी भी मनमाने ढंग से मान्यता नही प्राप्त है। किसी पद के उन्मूलन का औपचारिक आदेश नहीं है, इस सवाल का निर्णायक कि क्या पद को तथ्यात्मक रूप से समाप्त कर दिया गया है। इन टिप्पणियों से याचिकाकर्ताओं को परीक्षा के दौरान कोई सहायता नहीं मिलती है रिकॉर्ड के अनुसार, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधिसूचना दिनांक 13 मई, 2005 किसी भी मनमानी से पीड़ित नहीं है।

(55) अब हम श्री पटवालिया के राजनीतिक भाषणों और अखबार के बारे में रिपोर्ट पर विचार कर सकते हैं। हम सबमिशन भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यह एक बसेरा है कि अखबार का कोइ न्यायिक नोटिस नहीं लिया जा सकता है। राजनेताओं या राजनीतिक दलों द्वारा किए गए दावे अभियान की अवधि उसी श्रेणी में आएगी। हम समर्थन आकर्षित करते हैं कि हमारे सर्वोच्च के निम्नलिखित टिप्पणियों से पूर्वोक्त राय के मामले में लक्ष्मी राज शेट्टी और एक अन्य *बनाम* राज्य का तमिलनाडु (52) है।

> "25हम एक में बताए गए तथ्यों की न्यायिक सूचना नहीं ले सकते, जब तक यह पुक्ता सबूत से साबित नहीं होते । समाचार आइटम हार्दिक माध्यमिक की प्रकृति में है। अखबार धारा 78 (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों में से एक मे नहीं है। जिसके द्वारा तथ्य का आरोप साबित किया जा सकता है। धारा 81 के तहत संलग्न वास्तविकता का अनुमान अखबार की रिपोर्ट के साक्ष्य अधिनियम का इलाज, उसमें बताए गए तथ्यों के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है।
>
> 26. अब यह अच्छी तरह से कहा गया है कि वास्तव में अखबार मे निहित बयान केवल हियरसे है और बयान के निर्माता की अनुपस्थिति में अदालत और न पेश होना से माननीय नही है।
>
> अखबार की रिपोर्टों की स्वीकार्यता पर सवाल है इस न्यायालय द्वारा निपटा गया सामंती एन. बालाकर्ष्ण *बनाम* जॉर्ज फर्नांडीज, (1969) 3 एससीआर 603: (एआईआर 1969

(52) AIR 1988 SC 1274

एससी 120(1). वहाँ सवाल उठा कि क्या श्री जॉर्ज फर्नांडीज, सफल उम्मीदवार संसद में लौट आए बॉम्बे दक्षिण संसदीय संविधान से, शिवाजी पार्क में एक भाषण दिया, जिसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया, जो मराठा में रिपोर्ट की गई, जो परिचालित मराठी बॉम्बे में अखबार है और कहा गया :

"एक अखबार की रिपोर्ट बिना किसी सबूत और गवाहों के कोई मूल्य नहीं रखती है। यह ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे हाथ का माध्यमिक सबूत है। यह सर्वविदित है संवाददाताओं ने जानकारी एकत्र की और इसे संपादक को सौंप दिया जो समाचार आइटम संपादित करता है और फिर इसे प्रकाशित करता है। इसमें प्रक्रिया, सत्य विकृत या विकृत हो सकता है। ऐसा समाचार आइटम को हालांकि खुद को साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है यदि उन्हें अन्य साक्ष्यों के साथ ध्यान में रखा जा सकता है अन्य सबूत जबरन हैं।"

(56) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य और अन्य *बनाम* चौधरी भजन लाल और दूसरा (53) में गया है: –

"22. वर्तमान मामले में, कोई सबूत नहीं दिया गया है अखबार की रिपोर्ट में निहित तथ्यों का विवरण, चौधरी भजन लाल द्वारा किसी भी इनकार की अनुपस्थिति होगी आवेदक को अपने दायित्व का निर्वहन करने से अनुपस्थित न करें प्रेस रिपोर्ट मे दिखाई देने वाले तथ्यों के बयान को साबित करना है।

(57) श्री पी.एस. पटवालिआ सीनियर वकील पूर्वोक्त विचार के हैं कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियों से पूरी तरह से जवाब मिलता है। हम भी नोटिस कर सकते हैं वर्तमान मामले में;, कोई सामग्री कथनों की सच्चाई के प्रमाण में रिकॉर्ड पर रखी गई है। इसलिए, इस न्यायालय के लिए अखबार की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुतियाँ को स्वीकार करना संभव नहीं होगा।

(58) श्री मेहतानी द्वारा दिए गए निर्णय भी देखे हो सकते हैं। जस्करन सिंह ब्रार (सुप्रा) के मामले में, एक पूर्ण बेंच ने मनोरंजक याचिका पोस्ट पर किए गए चयनों को चुनौती देने वाला एक जनहित याचिका की गुंजाइश पर विचार किया। खेल व्यक्तियों से पुलिस के उप अधीक्षक उत्कृष्ट है।

(53) AIR 1993 S.C. 1348

यह माना जाता था कि इस तरह की रिट याचिकाएं बनाए रखने योग्य होंगी। निर्णय के पैरा 36 में गिरिश अरोरा की *(सुपरा),* कानून के सिद्धांतों की गणना की गई है। निष्कर्ष संख्या 36 (बी) नीचे देता है उस मामले में जहां नियुक्ति प्राधिकारी चयन एजेंसी की सिफारिशें स्वीकार नहीं करता है, यह रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य है, उसी स्थान पर जहाँ निर्णय के कारण और न्यायालय के समक्ष जब ऐसा करने के लिए कहा जाता है। वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं के पास पूर्वोक्त सिद्धांत का स्पष्ट रूप से अनुपालन है।

(59) किसी अन्य पर विचार करना आवश्यक नहीं होगा, इन के रूप में लर्नड एडवोकेट जनरल, हरियाणा द्वारा उद्धृत निर्णय केवल कानून के तय सिद्धांतों को दोहराते हैं, जो निर्णय के विभिन्न भागों में देखा गया।

(60) संपूर्ण सामग्री पर विचार करने पर, हम असमर्थ हैं कहने मे कि उत्तरदाताओं की कार्यवाही अनुचित है। जसपाल सिंह, सीनियर वकील ने एक संदर्भ बनाकर अपनी अधीनता का निष्कर्ष निकाला है, जो अंग्रेजी कोर्ट ऑफ अपील के जेनिसन *बनाम* बेकर, (54) पर निर्धारित है। उन्होंने विशेष निर्भरता रखी है लॉर्ड एलजे एडमंड की निम्नलिखित टिप्पणियों पर

> एक सवाल जो अब उठता है वह यह है कि क्या न्यायाधीश को प्रतिवादी को प्रतिबद्ध करने का अधिकार दिया गया था, ऑनरेबल जज कर्टिस-रालेघ के यादगार शब्द :
>
> "कानून को सीमित रूप से नहीं रहना चाहिए, जबकि जो लोग इससे सुरक्षा चाहते हैं, वे उम्मीद खो देते हैं।"

(61) पूर्वोक्त टिप्पणियों के आधार पर, उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को मैन्डेमस प्रकृति में एक रिट जारी करनी चाहिए,चयनित उत्तरदाता को नियुक्तियां देने का निर्देश देना चाहिए। हम पूर्वोक्त में व्यक्त भावना से पूरी तरह सहमत हैं। हम वास्तव में इसे उपयुक्त मामले में लागू करेंगे। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह शायद लागू नहीं होगा। इसलिए, हम श्री जसपाल सिंह की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं।

(62) उपरोक्त के मद्देनजर, हमें इनमें कोई योग्यता नहीं मिलती, रिट याचिका खारिज कर दी जाती हैं। लागत नहीं ।

R.N.R.

(54) ऑल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट्स (1972) 1 पेज 996

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा